

वामरुकार

अफोर्डेबल स्कूलिंग, कमेंडबल लर्निंग

वॉल्यूम 6 संस्करण 4 | अक्टूबर - नवंबर 2022

फण्ड स्टूडेंट
नॉट स्कूल्स

DBT

A Revolutionary Tool For
Reforms in Education

Healthy Education Begins at School



AddressHealth Education

A workbook-based health education program for schools

- Focused on health and behavior skills
- Designed by public health experts, pediatricians, psychiatrists, doctors, dentists and psychologists
- Delivered by health professionals

- Covers students from Class 1 to 10
- Conducted through eight sessions spread over one academic year
- Worksheets and quizzes for every chapter

Our services: Medical Room, Health Education, Health Check & Mental Health Workshop.

Operating in: Bangalore | Delhi | Pune | Hyderabad

T: +91-80-22444232 | www.addresshealth.in

services@addresshealth.com | Follow us on: [f](#) [ig](#) [in](#) [yt](#)
phone no - 71928 49521

 **addresshealth**
Healthy children. Happy children.



क्या स्कूल वाउचर एक अनैतिक विचार है?

जब भी इस विचार पर चर्चा की गई है, इसे ज्यादातर अनैतिक माना जाता है। हालांकि हमारे पास इस विचार का समर्थन करने वाले पुख्ता सबूत और सफलता की कहानियाँ हैं, लेकिन हमारी विचारधारा हमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के महत्व को समझने से रोकती है।

मान लीजिए कि आप भविष्य में किसी सरकारी स्कूल के पास से गुजर रहे हैं, अगर आप छात्रों को स्कूल की चारदीवारी फांदकर भागते हुए देखते हैं, शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे हैं, राजनेता यह दावा कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में कभी नहीं भेजेंगे, और छात्र मिड-डे-मील भोजन का सेवन करने से मर रहे हैं। अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछें कि ऐसा क्यों होता है। और क्या किया जा सकता है? आइए समझने की कोशिश करें कि स्कूल वाउचर हमारी शिक्षा प्रणाली की सभी मौजूदा समस्याओं के समाधान में से एक है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, स्कूल केवल सरकार के प्रति जवाबदेह है, छात्रों या उनके माता-पिता के प्रति नहीं। धन की एक स्थिर धारा, पारदर्शिता की कमी, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन की कमी के रूप में कोई

आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कम आय वाले माता-पिता भी बुनियादी जरूरतों को त्यागते हैं और दबाव महसूस करते हैं तथा अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करके अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं।

अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए भुगतान करते हैं। सरकार द्वारा राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के लिए पर्याप्त धन जारी रखने के बावजूद, यहाँ कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। अब समय आ गया है कि हम इन संस्थानों को वह शिक्षा देने के लिए कदम उठाएं जिसका हमारे नेताओं ने हर चुनाव में हमारे छात्रों से वादा किया है।

इस संस्करण में, पाठकों को शिक्षा प्रणाली में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मॉडल के महत्व के मूल मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ लेखकों जैसे शोधकर्ताओं, स्कूल मालिकों, अभिभावकों, छात्रों और नीति सलाहकारों ने पाठकों को शिक्षा में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के प्रभाव को समझाने के लिए अपने विचार रखे हैं। स्कूल नहीं, फंड स्टूडेंट्स का विचार हमारी शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।



हम 1 लाख बजट निजी स्कूलों की आवाज हैं

65 राज्य संघ

10 लाख शिक्षक

20 करोड़ छात्र

भारत के 26 राज्यों में

नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस - (निसा) देश भर के निजी बजट प्राइवेट स्कूलों और राज्य संघों का एक राष्ट्रीय स्तर का अलायंस है, जो देश भर के निजी बजट प्राइवेट स्कूलों को, जो कानून और उप-नियम उनके ऊपर लागू होते हैं, के बारे में और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए, उन्हें एकीकृत आवाज देने के लिए, और दिन-प्रतिदिन के शिक्षण और सीखने की प्रथाओं में गुणवत्ता सुधार की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें एक मंच पर लाता है।

Follow us on:

f /nisaedu

ig /nisaedu

tw /nisaedu

in /nisaedu

yt /Nisa Education

कंटेंट एडिटर

नंदिता सिंह

अनिल मौर्य

डिजाइन

अमन कुमार चौरसिया

वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 590

संपादकीय कार्यालय

यूनिट नंबर-501, 502, 503,

5वीं मंजिल, एच 1ए/1 सेक्टर

63, नोएडा उत्तर प्रदेश -

201301

फोन: 0120 4272234

मोब: +91 7669078760

www.nisaindia.org

बिक्री, सदस्यता, विज्ञापन या किसी
अन्य प्रश्न के लिए,
संपर्क करें: info@nisaindia.org

विषय सूची

संपादकीय

स्कूल वाउचर: छात्रों और अभिभावकों की आवाज और पसंद
नंदिता सिंह

अध्यक्ष का सन्देश

भारत की स्कूली शिक्षा को मापना

डॉ कुलभूषण शर्मा

शिक्षा

स्कूल वाउचर एक काम

डॉ पार्थ जे शाह और सुश्री बैशाली बोमजान

भारतीय शिक्षा प्रणाली का अर्थशास्त्र

विजय कुमार शाह

भारत की शिक्षा प्रणाली को ठीक करने की जरूरत है। क्या स्कूल वाउचर हो सकते हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना देश में एक बड़ी चुनौती है।

अपेक्षा वार्षिक

कर्नाटक का 'निवारक प्रोटोकॉल' सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में कैसे मदद कर सकता है?

कात्यायनी चामराज

एडवोकेसी

कंबोडिया के फ्लोटिंग स्कूल

नंदिता सिंह

स्कूल विकास योजना

eN-READ द्वारा पुस्तक समीक्षा, गुड नाइट टिंकू!

प्रदीप कुमार

स्टूडेंट कॉर्नर

भार्गवी शर्मा

राष्ट्रीय और राज्य गतिविधियाँ

मीडिया

निसा पदाधिकारी

निसा एसोसिएशन के सदस्य

निसा सदस्यता फॉर्म



नंदिता सिंह
संपादक, निसा

स्कूल वाउचर: छात्रों और अभिभावकों की आवाज और पसंद

शिक्षा की बढ़ती मांग के बावजूद संसाधनों की कमी बनी हुई है। अधिकांश देशों में एक सरकार, एक प्रमुख फाइनेंसर और शिक्षा की एक प्रमुख प्रदाता दोनों हैं। इसके बावजूद, स्कूली शिक्षा समाज के सभी सदस्यों तक समान रूप से नहीं पहुँचती है।

शिक्षा के वित्तपोषण के लिए, परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करने के लिए अपने बच्चों के नामांकन के आधार पर वाउचर या धन प्राप्त कर सकते हैं। वाउचर कार्यक्रम का लक्ष्य इन अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी धन का विस्तार करना है ताकि सभी माता-पिता को, पैसे की परवाह किए बिना, स्कूल का चयन करने का अवसर मिल सके जो उनकी प्राथमिकताओं के अनुकूल हो।

स्कूल की पसंद के वाउचर अक्सर शैक्षिक प्रणाली में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में विपणन किए जाते हैं। जब स्कूल, सार्वजनिक और निजी दोनों, छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और लागत में कटौती करते हुए गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा का परिणाम दक्षता लाभ होगा। सिद्धांत यह है कि निजी स्कूलों को विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने से, वे नवीन बनेंगे और इस प्रकार शैक्षिक प्रक्रिया में वृद्धि होगी। निजी स्कूलों के समान, पब्लिक स्कूलों का उद्देश्य छात्रों और उनके द्वारा लाए जाने वाले संसाधनों के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने मानकों को ऊपर उठाना है। दूसरी ओर, यह भी तर्क दिया जाता है कि वाउचर सिस्टम के तहत निजी प्रदाताओं को करदाताओं या आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। उनका तर्क है कि पसंद की अनुमति देने से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, शैक्षिक प्रणाली की सरकार की निगरानी कम होगी और अलगाव बिगड़ेगा।

स्कूल वाउचर का इतिहास

यह **मिल्टन फ्रीडमैन का प्रतिष्ठित पेपर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन** था जिसने शिक्षा वाउचर के विचार को जन्म दिया, जो बाद में 1990 के दशक में मिल्वौकी का पेरेंटल चॉइस प्रोग्राम बन गया। बाद के अनुभवजन्य अध्ययनों के अनुसार, जो छात्र एक निजी स्कूल में भाग लेने के लिए वाउचर का इस्तेमाल करते थे, उनके बेहतर स्कोर करने, हाई स्कूल से स्नातक होने और कॉलेज में दाखिला लेने की संभावना अधिक थी। लगभग सभी यूरोपीय देश हैं जो सार्वजनिक व्यय दक्षता का लाभ उठाने के लिए स्कूल पसंद का समर्थन करते हैं, और बेल्जियम, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसे देशों में, स्कूल पसंद एक संवैधानिक अधिकार है। सबसे कम सामाजिक आर्थिक स्तरों पर नामांकन बढ़ाने के लिए चिली, कोलंबिया और कैमरून ने भी शिक्षा वाउचर मॉडल को अपनाया है।

इसने छात्रों के व्यवहार के परिणामों में सुधार किया, जिसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध शामिल हैं, कक्षा में नाटकीय रूप से व्यवधान कम हुए

हैं, और लंबी अवधि में समाज में हिंसा की डिग्री भी कम हुई है। इसने हाई स्कूल के छात्रों की संज्ञानात्मक उपलब्धियों को भी बढ़ाया।

सामान्य तौर पर, वाउचर प्रोग्राम को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: लक्षित और सार्वभौमिक।

कोलम्बिया में लक्षित वाउचर योजना मौजूद है। आबादी के सबसे गरीब तीसरे हिस्से को माध्यमिक स्कूल तक पहुंच प्रदान करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा कवरेज के विस्तार के लिए कार्यक्रम (पेस) 1991 में स्थापित किया गया था। कार्यक्रम की अत्यधिक मांग के कारण, निजी स्कूलों के लिए वाउचर उन बच्चों को दिए गए, जिन्होंने एक लॉटरी। PACES को शेष 80% के लिए संघीय सरकार से धन प्राप्त हुआ, शेष 20% नगरपालिका सरकारों से प्राप्त हुआ। कार्यक्रम, जिसमें 216 समुदायों में 125,000 बच्चे शामिल थे और 1997 तक चले, को लागू किया गया। भाग लेने वाले निजी स्कूलों में प्रति छात्र एक इकाई लागत थी जो कि निजी स्कूलों की तुलना में 40% कम थी। लॉटरी वितरण ने शोधकर्ताओं को फ्री-फॉर्म प्रयोग करने का मौका दिया। जाँच के निष्कर्षों से पता चला कि वाउचर प्राप्त करने वालों के पास शिक्षा का उच्च स्तर है।

गैर-वाउचर छात्रों की तुलना में, वाउचर छात्रों की ग्रेड दोहराने की संभावना 6 प्रतिशत कम थी; उन्होंने उपलब्धि परीक्षणों पर 0.2 मानक विचलन अधिक स्कोर किया और कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की संभावना 20 प्रतिशत अधिक थी। उनकी शादी होने की संभावना भी कम थी और वे मजदूरी में अधिक कमाते थे।

दूसरी ओर **चिली** में 1980 से यूनिवर्सल वाउचर कार्यक्रम लागू है। अपने स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर, प्रत्येक शहर को एक अद्वितीय मासिक अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका



सरकार छात्रों को उनके माता-पिता की पसंद के सब्सिडी वाले निजी स्कूलों में भाग लेने के लिए भुगतान करती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के समायोजन के बाद, परीक्षण स्कोर दोनों के बीच तुलनीय हैं, लेकिन सब्सिडी वाले निजी स्कूलों में इकाई खर्च सस्ता है। चिली की वाउचर योजना का अध्ययन गहन जाँच के दायरे में आ गया है। पूरी तरह से प्रभाव मूल्यांकन या यादृच्छिक परीक्षणों की कमी के बावजूद, प्रणाली व्यापक शोध का विषय रही है, सफलता की अलग-अलग डिग्री के साथ। कुछ को कोई प्रभाव नहीं मिलता है, दूसरों को बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं मिलता है, कुछ मामूली औसत उपचार प्रभाव पाते हैं, जबकि कुछ बड़े उपचार प्रभाव पाते हैं। एक अध्ययन में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वाउचर कार्यक्रम से छँटाई में वृद्धि होती है, क्योंकि "सर्वश्रेष्ठ" पब्लिक स्कूल के छात्र निजी क्षेत्र में चले जाते हैं।

एक अन्य राष्ट्र जो कूपन के मूल्य को प्रदर्शित करता है, वह है नीदरलैंड। सरकारी वित्त पोषण वाले निजी स्कूलों में 70% छात्रों का नामांकन होता है। जब उन घरों की तुलना में जहाँ छात्र पब्लिक स्कूल में जाते हैं, ये छात्र आम तौर पर निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के घरों से आते हैं, हालांकि वे अधिक परीक्षा स्कोर प्राप्त करते हैं। प्रति छात्र सरकार के निश्चित वित्तपोषण (साथ ही वंचित बच्चों के लिए अतिरिक्त धन) के साथ संयुक्त विकल्पों की माता डच स्कूलों को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, ग्रेड मुद्रास्फीति का कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि संस्थानों को उपलब्धि प्रदर्शित करके छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।

इन उदाहरणों से पता चलता है कि कैसे वाउचर राष्ट्रों को उनकी शैक्षिक प्रणालियों को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन वे एक निश्चित सेटिंग में ऐसा करते हैं।

निजी स्कूलों की कहानी

निजी स्कूलों में 70% विद्यार्थियों द्वारा 1,000 रुपये से कम शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो राज्य के सरकारी स्कूलों की तुलना में पाँच गुना कम खर्चीला है। निजी स्कूलों में नामांकन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे कठिन समय में, वाउचर लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए जीवन समर्थन प्रणाली के रूप में काम करेंगे।

इसके अतिरिक्त, निजी स्कूलों पर निरीक्षण, मान्यता और पिछले वर्ष की ट्यूशन फीस के देर से भुगतान के बारे में सख्त नियम और शिक्षा अधिकारियों का हस्तक्षेप लागू होता है। बजट निजी स्कूलों को कोविड-19 की वजह से काफी नुकसान हुआ है।

महामारी। घटते वित्तीय संसाधनों के कारण उनमें से बड़ी संख्या में बंद हो गए थे। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स एलायंस के अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने कहा कि कोविड-19 संकट और निजी स्कूलों में घटते नामांकन के परिणामस्वरूप, कई स्कूल 18 महीने से अधिक समय से बंद हैं।

सोशल इंपैक्ट कंसल्टिंग फर्म एफएसजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा वाउचर मॉडल 2.7 लाख से अधिक एपीएस के लिए राजस्व का नया स्रोत होगा, जो देश के 80 मिलियन स्कूली छात्रों में से 40 प्रतिशत की सेवा करता है। इसके अलावा, वाउचर मॉडल ऑनलाइन शिक्षा और लंबित वेतन के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों में सुधार करेगा।

वर्ग और जाति के बंधन को तोड़ना

वर्ग और जाति समाज का स्त्रीकरण कमजोर होगा, जो एक अनपेक्षित दीर्घकालिक परिणाम है। युवा छात्र के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के अन्य छात्रों के संपर्क में आना फायदेमंद होगा, ताकि पूर्वकल्पित धारणाओं को चुनौती दी जा सके। ये वाउचर माता-पिता को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भुगतान करने, बाल श्रम पर महामारी के विशेष रूप से स्पष्ट प्रभावों और बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने की दर को रोकने की अनुमति देते हैं। जवाबदेही का संयोजन और संबंधित सभी पक्षों के लिए एक उपयुक्त प्रोत्साहन प्रणाली की अभी आवश्यकता है।

शिक्षा वाउचर माता-पिता को सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक सरल लेकिन आवश्यक वित्तीय उपकरण है, जिसे उनके निजी या सार्वजनिक, उनके चयन के स्कूलों में छोड़ा जा सकता है, जिसके आधार पर वे मानते हैं कि वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नई संरचना के साथ, राज्य अब सीधे पब्लिक स्कूलों को धन नहीं देता है, बल्कि माता-पिता को सर्वश्रेष्ठ छात्रों के लिए संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा के एक स्वस्थ चक्र को बढ़ावा देने के लिए चयन करने की शक्ति प्रदान करता है। स्कूल एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की अपनी प्रतिस्पर्धा में मौलिक पठन और संख्यात्मक कौशल पर अधिक जोर देंगे। यह ठोस परिणामों का प्रदर्शन, छात्रों के प्रदर्शन में सुधार और उनके संज्ञानात्मक और तकनीकी कौशल को बढ़ाकर किया जाएगा।

विश्वसनीय नीति थिंक टैंक की मदद से, आंध्र प्रदेश और दिल्ली की राज्य सरकारों ने अतीत में पायलट शिक्षा वाउचर कार्यक्रम चलाए हैं। NIPUN भारत और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) दोनों का उद्देश्य सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना है।



भारत की स्कूली शिक्षा को मापना



डॉ कुलभूषण शर्मा
अध्यक्ष, निसा

इस विचार को व्यापक रूप से माना जाता है कि बच्चों को स्कूल तक समान पहुंच होनी चाहिए। बच्चे के जन्म से सामाजिक वर्ग, जातीयता और लिंग का उनके भविष्य की संभावनाओं पर कोई नैतिक असर नहीं होना चाहिए। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, जिसे भारत ने 2015 में स्वीकार किया, में "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने" की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) शामिल है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के शिक्षा कार्यक्रमों, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नामांकन दर में वृद्धि और ड्रॉपआउट दरों में कमी पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। सरकार, हालांकि, इस मुद्दे का समाधान नहीं करती है कि सभी स्कूल समान डिग्री की शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। एक सरकारी स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता उसी राज्य के एक निजी स्कूल से भिन्न हो सकती है।

हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी गई है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, यह दुविधा तब उभरती है। इस व्यापक रूप से प्रचलित मुद्दे का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में एक संभावित समाधान हो सकता है। शिक्षा में डीबीटी न केवल अवसर समानता की गारंटी देगा बल्कि शिक्षा पर सरकारी खर्च की प्रभावशीलता में भी सुधार करेगा। छात्र अपनी पसंद के किसी भी स्कूल में जा सकते हैं,

शैक्षिक खर्चों और वाउचर को कवर करने वाले सीधे वित्तीय हस्तांतरण के लिए धन्यवाद।

मौजूदा स्थिति के विपरीत, पसंद की बढ़ी हुई स्वतंत्रता के साथ, निजी और सरकारी दोनों स्कूल सभी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। वर्तमान प्रणाली के अनुसार, केवल आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्र सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जबकि अमीर परिवारों के लोग निजी संस्थानों में जाते हैं। इसने एक दुष्क्रम बना दिया है जो वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को उनकी वर्तमान जीवन शैली जीने में मदद करता है।

भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लक्ष्य के साथ, NEP से भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की उम्मीद है। NEP 2020 शिक्षा वितरण की गुणवत्ता को लगातार बढ़ाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि यह रणनीति सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप से प्रगतिशील है, यह इसके कार्यान्वयन पर चर्चा करने की अपेक्षा करती है और नागरिक समाज संगठनों की कई सिफारिशों के बावजूद, डीबीटी के महत्व को पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं करती है। एनईपी 2020 भारत की बढ़ती युवा आबादी का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति साबित हो सकती है अगर इसे डीबीटी और अन्य कार्यान्वयन-उन्मुख पहलों के साथ जोड़ा जाए।



स्कूल वाउचर एक काम

पार्थ जे शाह और बैशाली बौमजन ने कहा, सरकारी स्कूलों को जवाबदेह बनाने के लिए स्कूल वाउचर सबसे शक्तिशाली साधन है।



डॉ पार्थ जे शाह
संस्थापक
सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी



श्रीमती बैशाली बौमजन
मैनेजर - पीआर एंड कम्युनिकेशंस,
शिक्षा, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

भारतीय शिक्षा प्रणाली पहुंच और आवृत्त क्षेत्र प्रदान करने में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है और सालाना 41,978 करोड़ रुपये खर्च करती है। यह आंकड़ा प्रभावशाली है, लेकिन हम सभी बहुत दर्द से जानते हैं कि इस प्रणाली में अक्षमताएं बहुत अधिक हैं। हमारी आकांक्षाओं और जमीनी उपलब्धियों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जो करदाताओं के पैसे के लिए खराब हिसाब की जिम्मेदारी को दर्शाता है।

वर्तमान प्रणाली में, बड़ी संख्या में सर्व शिक्षा अभियान का दावा करने के बावजूद, स्कूल केवल सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, न कि प्राथमिक लाभार्थियों - छात्रों और उनके माता-पिता के प्रति। धन के एक सुनिश्चित प्रवाह, पारदर्शिता की कमी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी स्कूलों को अधिक छात्रों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिए जाने के कारण जो शालीनता पैदा हुई है, उसके परिणामस्वरूप घटिया शिक्षा का वितरण हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गरीब माता-पिता भी बुनियादी जरूरतों को त्यागने और अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वर्ग बजट प्राइवेट स्कूल है, जिसकी फीस 50-300 रुपये प्रति माह है, जहाँ फेरीवालों, निर्माण श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। दूसरी ओर, सरकार राज्य के स्कूलों पर बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना जारी रखती है, और अब समय आ गया है कि हम इन स्कूलों को वितरित करने के लिए कुछ करें - न केवल स्कूली शिक्षा, बल्कि वास्तविक शिक्षा। यह अभी होना चाहिए, न कि अगली राष्ट्रीय शिक्षा नीति या पंचवर्षीय योजना में।

राज्य के स्कूलों को अच्छी तरह से संचालित करने का एकमात्र तरीका उन्हें छात्रों और अभिभावकों के प्रति जवाबदेह बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन स्कूल वाउचर से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है।

स्कूल वाउचर क्या है?

स्कूल वाउचर एक नीति सुधार विचार है, जो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा विकसित किया गया है, ताकि माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भुगतान करने के साधन देकर जिम्मेदारी से स्कूली शिक्षा में शामिल किया जा सके।

स्कूल वाउचर सरकार द्वारा गरीबों की शिक्षा के लिए वित्त पोषण करने के तरीके को बदल देता है। यह सरकार द्वारा दिया जाने वाला कूपन है जो छात्र की पसंद के स्कूल में शिक्षा की पूर्ण या आंशिक लागत को कवर करता है। स्कूल छात्रों से वाउचर एकत्र करते हैं, उन्हें अपने बैंक खातों में जमा करते हैं और बैंक फिर स्कूल के खातों में सरकार के खाते से डेबिट करते हुए बराबर धन के साथ क्रेडिट करते हैं। कोई पैसा वास्तव में हाथ नहीं बदलता है; केवल वाउचर छात्र से बैंक में जाता है, और फिर वापस सरकार के पास जाता है।

स्कूल वाउचर का वैश्विक अनुभव?

दुनिया भर के कई देशों में कई सफल वाउचर कार्यक्रम हैं, जैसे कि चिली, आइवरी कोस्ट, स्वीडन, यूएसए, डेनमार्क और चेक गणराज्य में विविधता है जो न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पसंद के प्रभाव और स्कूलों के



बीच परिणामी प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं, बल्कि गरीब परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूलों की क्षमता भी।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्तर पर स्वीडन की वाउचर प्रणाली समुदाय में सार्वजनिक और आत्मनिर्भर स्कूलों के बीच मुफ्त विकल्प को सक्षम बनाती है, और इससे पब्लिक स्कूलों में शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार हुआ है। इसके सार्वभौमिक वाउचर कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक बच्चा, परिवार की आय के बावजूद, वाउचर के लिए अर्हता प्राप्त करता है। हालांकि, अधिकांश अन्य देशों में, स्कूल वाउचर कम आबादी पर लक्षित होते हैं।

अमेरिका में, फ्लोरिडा का स्कूल पसंद कार्यक्रम, McKay छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विकलांग छात्रों के माता-पिता को अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक वातावरण चुनने की अनुमति देता है। यह भाग लेने वाले निजी स्कूल में भाग लेने के अवसर सहित विभिन्न विकल्प प्रदान करता है, या किसी अन्य पब्लिक स्कूल में स्थानांतरित करता है।

बांग्लादेश ने वाउचर के विचार को सीधे नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, जिसे आमतौर पर सशर्त नकद हस्तांतरण (सीसीटी) कहा जाता है। इसके महिला शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत लड़कियों में उच्च शिक्षा

छोड़ने वालों की दर के समाधान के रूप में की गई थी ॥ प्रत्येक बच्चा जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल की वार्षिक परीक्षा में अच्छी उपस्थिति और अंकों की शर्तों को पूरा करता है, उसके परिवार को सरकार से नकद मिलता है,

अधिक वास्तविक रूप से यह उसकी माँ के बैंक खाते में है कि निर्दिष्ट राशि का त्रैमासिक जमा किया जाता है। पैसा न केवल स्कूली शिक्षा की लागत को पूरा करता है, बल्कि माता-पिता को अपनी लड़कियों को स्कूलों में रखने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। इस योजना की सफलता के आधार पर लड़कों के बीच प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक समान कार्यक्रम शुरू किया गया है।

वाउचर सिस्टम किसी भी तरह से इस बात से इनकार नहीं करता है कि यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा शिक्षित हो। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को स्कूल चलाने के वास्तविक व्यवसाय में होना चाहिए, खासकर सरकारी स्कूलों से गरीब बच्चों की बढ़ती उड़ान को देखते हुए। वाउचर सिस्टम में, जैसा कि कई देशों में साबित हो चुका है, दो चीजें होती हैं। पहला, बुनियादी शैक्षिक निर्णयों पर अधिकार नौकरशाहों से माता-पिता को हस्तांतरित किया जाता है और दूसरा, स्कूल, निजी या सरकारी, कम आय वाले बच्चों के लिए भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होते हैं।

दिल्ली वाउचर परियोजना

स्कूल की पसंद को भारत में लाना: भारत का पहला स्कूल वाउचर प्रोजेक्ट

दिल्ली में 28 मार्च, 2007 को सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी (CCS) द्वारा अपने स्कूल च्वाइस कैम्पेन (SCC) के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। स्कूल च्वाइस की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, SCC ने दिल्ली के 68 वार्डों में 408 छात्रों को प्रति वर्ष 3,600 रुपये तक के स्कूल वाउचर प्रदान किए। 157 दिल्ली वाउचर प्रोजेक्ट (DVP) स्कूल हैं, और भाग लेने वाले सभी स्कूल लाभार्थियों, CCS द्वारा चुने जाते हैं, और इसलिए यह स्वैच्छिक हैं।

अभियान के दौरान, 50 से अधिक स्कूल च्वाइस कार्यक्रमकर्ता लगभग 12 लाख अभिभावकों तक पहुंचे, क्योंकि अभियान वैन वाउचर फॉर्म वितरित करने और प्रस्तुतियाँ देने के लिए चल रही थी। 1.2 लाख से अधिक अभिभावकों ने CCS स्कूल वाउचर के लिए आवेदन किया! गरीबों की पहचान कैसे करें, इसकी चिंता करने के बजाय, किसी भी छात्र को जो वॉचर के लिए योग्य सरकारी स्कूल में नामांकित किया गया था। वाउचर कम से कम तीन साल (2007-08 से 2009-10) की अवधि के लिए दिए गए हैं। हालांकि, एससीसी आगे भी छात्रों का समर्थन करना जारी रखेगी, यदि धन उपलब्ध हो।



एक लाख से अधिक आवेदकों में से छात्रों के चयन की एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के रूप में, एससीसी ने प्रत्येक वार्ड में 12 छात्रों को चुनने के लिए स्थानीय वार्ड पार्षद के नेतृत्व में एक सार्वजनिक लॉटरी आयोजित की - पहली सूची के लिए छह और बफर सूची के लिए छह, यदि कुछ

पहली सूची में चुने गए छात्रों की पालता या स्वीकृति की समस्या थी।

26 जुलाई 2007 को, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व लेखक गुरचरण दास, कांग्रेस पार्टी के सदस्य नफीसा अली, और एक गैर सरकारी संगठन दीपालया के सचिव और मुख्य कार्यकारी टीके मैथ्यू ने स्कूल वाउचर से विजेता सम्मानित किया। इन 408 वाउचर छात्रों के लिए अपनी पसंद के स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना एक सपने के सच होने जैसा है। कुछ चिंताएँ हैं कि वाउचर आसानी से अर्ध-मुद्रा बन सकते हैं, और व्यापार योग्य वित्तीय साधनों के रूप में खरीदे और बेचे जा सकते हैं, लेकिन तकनीक में इतना सुधार हुआ है कि वाउचर को सुरक्षित उपकरण बनाना आसानी से संभव है। ठीक उसी तरह जैसे कई सरकारों और यहाँ तक कि निजी निगमों द्वारा पेश किए जाने वाले और हजारों प्रतिष्ठानों में स्वीकार किए जाने वाले खाद्य टिकट सुरक्षित हैं।

सफलता के संकेत

डीवीपी का स्वतंत्र मूल्यांकन: सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा डीवीपी के तीसरे पक्ष के आकलन ने बच्चों की सीखने की उपलब्धियों में काफी सुधार दिखाया है, और दिन-प्रतिदिन माता-पिता की भागीदारी में वृद्धि हुई है, जो तब शुरू

हुई जब माता-पिता को यह तय करना था कि कौन सा स्कूल अपने बच्चों के लिए चुनना है। पसंद की यह शक्ति जिसे वाउचर ने अनुमति दी है, अपने साथ माता-पिता की जिम्मेदारी और अधिक सक्रिय भागीदारी भी लाई है। संपूर्ण डीवीपी आकलन रिपोर्ट www.school Choice.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

कुल मिलाकर, वाउचर छात्रों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन निजी स्कूलों में गैर-वाउचर छात्रों के बराबर, अंग्रेजी, गणित और हिंदी में आयोजित तीनों परीक्षाओं में। वाउचर लाभार्थियों के 90 प्रतिशत से अधिक माता-पिता, जो अब निजी स्कूलों में जा रहे हैं, अपने बच्चों, उनके शिक्षकों की शैक्षणिक प्रगति और स्कूलों में अनुशासन के मानक से खुश हैं।

वाउचर प्रणाली कमजोर सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करने और छात्रों को बनाए रखने के लिए निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करेगी। इस अर्थ में, प्रणाली सरकार विरोधी और निजी समर्थक नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धा और विकास समर्थक है; और अंतिम उद्देश्य यह है कि गरीब बच्चों को उनके विशेषाधिकार प्राप्त समकक्षों के समान उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं मिलेंगी।

यदि सरकार गरीब माता-पिता को वाउचर प्रदान करना शुरू कर देती है, तो वे स्कूलों में अपने बच्चों के लिए और अधिक नवीन और मूल्य वर्धित सुविधाओं की मांग करने में सक्षम होंगे। अब तक, सरकारी स्कूल अपने छात्रों को बनाए रखने और एक तरफ नामांकन बढ़ाने और दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ मध्याह्न भोजन प्रदान करते हैं; हालांकि यह बहस का विषय है कि क्या इन्हें पूरा किया जा रहा है।

हम भी आशान्वित हैं और श्री लवली के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं जिन्होंने डीवीपी रिपोर्ट के विमोचन के दौरान सार्वजनिक रूप से इस विचार का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, 'वाउचर का सुझाव' बहुत अच्छा है। भविष्य में स्कूलों के बजाय छात्रों को वित्त पोषित करना होगा। दिल्ली सरकार छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप फीस में वृद्धि से निपटने के लिए गरीब माता-पिता की मदद करने के लिए जल्द ही वाउचर विचार का उपयोग करेगी।

पहली पहल पर निर्माण

पहले वाउचर पायलट प्रोजेक्ट के इन निष्कर्षों ने हमें वाउचर सुझाव को और आगे ले जाने और एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया है - इस बार विशेष रूप से लड़कियों के लिए। जुलाई 2009 में शुरू की जाने वाली यह परियोजना चार साल की अवधि के लिए 400 लड़कियों को वित्त पोषित करेगी और पांचवीं कक्षा तक उनकी शिक्षा की लागत को कवर करेगी। पूर्वी दिल्ली के चयनित वार्डों में गरीब परिवारों की कक्षा II की लड़कियाँ वाउचर के लिए पात्र होंगी और उन्हें प्रति वर्ष 4,000 रुपये तक के वाउचर प्राप्त होंगे।

प्रगतिशील राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विशिष्ट समस्याओं के लिए नवीन समाधान तैयार करने के लिए स्कूल पसंद के विचारों को अपनाना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने दो योजनाओं की घोषणा की है जो स्कूल वाउचर का उपयोग करती हैं - ज्ञानोदय योजना, एक बिल्ड, ऑपरेट और ओन बीओओ (बीओओ) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत छठी से बारहवीं कक्षा के लिए नए स्कूल खोलने की सुविधा के लिए, जिसमें 50 इन स्कूलों में सीटों का प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा स्कूल वाउचर के माध्यम से प्रायोजित किया जाएगा; दूसरी योजना शिक्षक का अपना विद्यालय है, जो शिक्षकों को राज्य के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी, एक शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों को अपनाने और पीपीपी मार्ग के माध्यम से नए स्कूल खोलने की सुविधा प्रदान करती है।

उत्तराखंड में, 'पहल', एक अभिनव (पीपीपी) पहल, 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा वाउचर प्रदान कर रही है, जो देहरादून की मलिन बस्तियों में कूड़ा बीनने वाले, मैला ढोने वाले, सपेरे और अनाथ थे। यह पहल एक बड़ी सफलता रही है और अब इसका विस्तार नैनीताल, और उधम सिंह नगर जिलों में हो गया है।

आप देखना चाहते हैं परिवर्तन होना

एक गैर-विद्यालय पसंद प्रणाली को आसानी से एक स्कूल पसंद प्रणाली में कैसे बदला जा सकता है? चूंकि यह एक प्रणालीगत परिवर्तन है, यह पायलट परियोजनाओं के साथ शुरू हो सकता है और फिर दायरे और आकार में बढ़ सकता है। इस तरह के वाउचर पायलट परियोजनाओं को विशेष क्षेत्रों या समुदायों की जरूरतों के अनुरूप निम्नलिखित तरीकों से संरचित किया जा सकता है:



- पुनर्वास कॉलोनियों या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कोई सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ निजी स्कूल मौजूद हैं, जैसे पेरी-शहरी क्षेत्रों में वाउचर पायलट का संचालन करें। जबकि यहाँ नए सरकारी स्कूलों के निर्माण में समय लगेगा, इन बच्चों की स्कूली शिक्षा की समस्या को तुरंत दूर करने की जरूरत है। तो, स्कूल वाउचर एक तेज, न्यायसंगत और कुशल समाधान होगा।
- एक राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के सभी नए सरकारी स्कूलों को केवल वाउचर के माध्यम से निधि देने का निर्णय ले सकती है। इन नए स्कूलों को उनके द्वारा आकर्षित और बनाए रखने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर उन्हें वित्त पोषण के बदले में उनके संचालन में अधिक स्वायत्तता दी जा सकती है। यह शहरी भारत में स्कूली शिक्षा में क्रांति लाएगा।
- उन क्षेत्रों में जहाँ स्कूलों की आपूर्ति एक पुरानी समस्या है, नए स्कूलों में 50-75 प्रतिशत छात्रों को उदार वाउचर के माध्यम से निधि देने का वादा अधिक स्कूलों को आकर्षित कर सकता है। आइए 100 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों का चयन करें और एक उदार वाउचर कार्यक्रम लागू करें।
- बेहतर निजी स्कूलों में जाने के लिए वाउचर देकर सड़क पर रहने

वाले बच्चों, कूड़ा बीनने वालों और अन्य जटिल स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करें। चूंकि निजी स्कूलों को पैसा तभी मिलेगा जब छात्र रहेंगे और पढ़ेंगे, स्कूल बच्चों को रखने के लिए सभी आवश्यक चीजें करेंगे।

अभियान के राजदूत के रूप में, समुदाय के प्रमुख नेता जैसे दास, माधव चौवन (निदेशक, प्रथम), प्रोफेसर पीवी इंदिरासन (पूर्व निदेशक, आईआईटी चेन्नई), और अन्य स्कूल पसंद विचारों के मुखर समर्थक रहे हैं; और देश भर में बड़े पैमाने पर वाउचर पायलट परियोजनाओं का पुरजोर समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हालाँकि, जबकि सरकार बहस करती है, निजी क्षेत्र वाउचर पायलटों का समर्थन करने का बीड़ा उठा सकता है। कई निगमों ने लंबे समय से अनुदान और छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा के कारण का समर्थन किया है। अगर हम इतने सारे निगमों से इस पैसे को एक आम भारत वाउचर फंड में परिवर्तित करते हैं तो बड़े पैमाने पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। ये पायलट हमारे लिए आवश्यक अनुभव उत्पन्न करेंगे और सरकारों को आगे बढ़ने का विश्वास दिलाएंगे। भारत में सभी बच्चों को पसंद की शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए आम मिशन में शामिल हों।

यह लेख 29 जुलाई 2009 को सीएफओ कनेक्ट में प्रकाशित हुआ था।



भारतीय शिक्षा प्रणाली का अर्थशास्त्र



विजय कुमार शाह
अध्यक्ष, भारतीय शिक्षण मंडल (उत्तरबंगा प्रांत)

भारत में लगभग 15,00,000 स्कूल हैं, जिनमें से 11,00,000 सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं और 4,00,000 निजी स्कूल हैं और छात्रों की कुल संख्या लगभग 25 करोड़ है। जहाँ हमारे देश के 53% छात्र 11 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वहीं 47% छात्र 4 लाख निजी स्कूलों में पढ़ते हैं।

सरकार द्वारा एकल किए गए आंकड़ों (DISE DATA) के अनुसार, 2011-2018 की अवधि के दौरान, 2,40,00,000 छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया और निजी स्कूलों में अपना नामांकन कराया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. अमर्त्य सेन के अनुसार यदि यही स्थिति रही तो सरकारी स्कूलों का अस्तित्व इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगा।

हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ केंद्र सरकार 100 रुपये का शिक्षा भत्ता देती है। 2,250/- प्रति माह अपने प्रत्येक कर्मचारी के बच्चों के लिए मोटी तनखाह के अलावा। क्या गजब का शासन है जिसमें केंद्र विद्यालय हैं और सरकारी सेवकों के बच्चों के लिए अतिरिक्त शिक्षा भत्ता है लेकिन जनता के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि लोक सेवक न केवल नियामक हैं बल्कि हमारे देश के सभी संसाधनों पर उनका अधिमान्य अधिकार भी है। सरकार सरकारी विद्यालयों में प्रति बच्चा 6,000 रुपये से अधिक खर्च करती है। इसके बावजूद उसमें कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके कारण अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं। क्या यह पक्षपातपूर्ण व्यवस्था बजट निजी स्कूलों में पढ़ रहे 12 करोड़ बच्चों के प्रति हमारी संवेदनहीनता को नहीं दर्शाती?

लगभग 47% (12 करोड़) छात्रों के साथ, भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा निजी स्कूली शिक्षा नेटवर्क है। जिस तरह से छात्रों द्वारा सरकारी स्कूलों को छोड़ा जा रहा है, इससे हमें 1,30,000 और निजी स्कूलों की आवश्यकता है।

गुणवत्तापूर्ण निजी स्कूलों की घटती संख्या के पीछे तीन मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

1. लाइसेंस राज : एक ईमानदार व्यक्ति के लिए आज स्कूल स्थापित करना कठिन है। अलग-अलग राज्यों में अनुमति और उनसे जुड़ी रिश्तों की संख्या 35 से लेकर 125 तक है। इन सभी कार्यवाहियों में 5 साल तक का समय लग सकता है।
2. आर्थिक तंगी : स्कूल चलाना अब लाभदायक नहीं रह गया है। यह समस्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने के साथ शुरू हुई, जहाँ सरकार ने गरीबों के लिए 25% सीटें आरक्षित की। इसके पीछे अच्छा तर्क था, लेकिन कार्यान्वयन

गड़बड़ा गया था। चूंकि राज्य सरकार कोई संतोषजनक मुआवजा प्रदान नहीं करती है, शेष 75% छात्रों के लिए शुल्क बढ़ जाता है। माता-पिता शिकायत करना शुरू कर देते हैं और कई राज्य फीस को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्कूलों की वित्तीय स्थिति में गिरावट आती है। स्कूलों को बंद करने के परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या कम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ स्कूल पहले से ही बंद हो चुके हैं और कई महामारी के बाद पालन करेंगे।

3. राष्ट्रीय पाखंड: कानून स्कूलों को मुनाफा कमाने से रोकता है, अभी भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 9 स्कूलों को अपनी कमाई से लाभ उठाने की अनुमति देती हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपने स्कूलों को शिक्षा में मुनाफा कमाने से रोकता है। यह नौटंकी बंद होनी चाहिए। इस क्षेत्र को 'गैर लाभप्रद' से 'लाभप्रद' बनाकर एक क्रांति लाई जा सकती है। यह निवेश के एक युग की शुरुआत करेगा जिसके परिणामस्वरूप अधिक विकल्प होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। जो माता-पिता बिजली, पानी और इंटरनेट आदि के लिए भुगतान कर रहे हैं, वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी भुगतान करेंगे।

ईमानदार निजी स्कूलों के स्थायित्व के लिए तथाकथित लाइसेंस राज को हटाने की भी जरूरत है। उन्हें आधुनिक देशों की तरह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शिक्षा में निवेश तभी किया जाएगा जब फीस या पाठ्यक्रम से संबंधित स्वतंत्रता होगी। केवल एक तिहाई निवेश वाले निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

एक अनुमान के अनुसार हमारी सरकारें (केंद्र और राज्य) सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की शिक्षा पर लगभग 6,000/- रुपये प्रति माह खर्च करती हैं। राशि का बड़ा हिस्सा शिक्षकों के अत्यधिक उच्च वेतन पर खर्च किया जाता है जो अक्सर उनके कार्य भार और दक्षता के अनुरूप नहीं होता है। वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश के कनिष्ठ सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का प्रारंभिक वेतन 48,918/- रुपये था, जो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 11 गुना अधिक था। भारत में लगभग 98% निजी स्कूल 3,000 रुपये प्रति माह से कम बजट के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। 70% माता-पिता 1000/- रुपये प्रति माह से कम फीस का भुगतान करते हैं। यह इस धारणा को गलत साबित करता है कि निजी स्कूल केवल संपन्न लोगों के लिए हैं।

एक मिथक है कि केवल सरकार ही अपने नागरिकों के लाभ के लिए शिक्षा प्रदान कर सकती है और इस प्रकार निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर निजी स्कूलों को अनुमति दी जाती है:

1. निजी स्कूलों को मुनाफा नहीं कमाना चाहिए।
2. इस तरह के स्कूल अक्सर अव्यावहारिक और कठोर कानूनों द्वारा इस आरोप का हवाला देते हुए जंजीरों में जकड़े जाते हैं कि वे महंगे और बेईमान हैं।

यह मिथक इस मिथ्या धारणा पर आधारित है कि आधुनिक देशों में सरकार शिक्षा प्रदान करती है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और स्कैंडिनेवियाई देशों ने शिक्षा में संशोधन के तहत निजी संस्थानों को प्रोत्साहित किया है। भारत ने इस मिथक के आधार पर सरकारी स्कूलों में निवेश किया है, लेकिन परिणाम दयनीय हैं।

वर्तमान शिक्षा नीति के आधार पर विद्यालयों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. सरकारी स्कूल
2. स्कूल सामाजिक या धार्मिक ट्रस्टों द्वारा चलाए जाते हैं
3. कॉर्पोरेट्स द्वारा संचालित स्कूल; बड़े स्कूल श्रृंखलाओं के लिए बड़े व्यापारिक परिवार
4. बजट निजी स्कूल जिनकी संख्या कम है और जो सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि से कम राशि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे शिक्षा के क्षेत्र में एक अविश्वसनीय योगदान देते हैं। शिक्षक इस योगदान का एक अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन इन स्कूलों की सराहना के बजाय प्रशासन के अमिल व्यवहार और उन पर इस्तेमाल किए गए मोटे शब्दों सहित कई समस्याएं उनकी परेशानी में इजाफा करती हैं।

कोरोना के बाद, भारत को और अधिक नवीन स्कूलों की आवश्यकता होगी और यह तभी संभव होगा जब हम उन्हें और अधिक स्वतंत्रता देंगे। यह ढोंग

से छुटकारा पाने और हमें और अधिक ईमानदार बनाने में मदद करेगा। हमारी प्रणाली अधिक कुशल और जवाबदेह होगी। स्कूल चलाने वाला व्यक्ति अब दोषी नहीं होगा या अव्यवहारिक कानूनों को तोड़ने से डरेगा और इसके बजाय स्कूल के प्रशासन में अपनी सारी ऊर्जा लगाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बारे में नहीं सोचा गया है। भारतीय शिक्षा में सुधार के दो आधार होने चाहिए।

1. सरकारी स्कूलों के स्तर और गुणवत्ता में सुधार।
2. निजी स्कूलों को अधिक स्वतंत्रता देना।

सरकार को नीचे सूचीबद्ध दो चीजों को अलग करने का प्रयास करना चाहिए:

1. स्कूलों की निगरानी और शिक्षा के खानपान।
2. सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल का प्रशासन।

सरकार को उनके स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए और सरकारी स्कूलों को उनकी संबंधित प्रबंध समितियों को सौंप देना चाहिए। स्कूलों पर समान कानून लागू होना चाहिए चाहे वे सरकारी हों या निजी। इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से शिक्षा भत्ते के रूप में प्रत्येक बच्चे को प्रति माह 2000 रुपये से 3000 रुपये की राशि आवंटित करनी चाहिए। इस प्रकार छात्रों को शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर विद्यालयों का चयन करने की स्वतंत्रता मिलेगी। सभी शिक्षा बोर्डों को परीक्षा आयोजित करनी चाहिए और परिणाम घोषित करना चाहिए। निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क लेने वाले विद्यालयों से सभी प्रकार के विशेषाधिकार वापस लिए जाने चाहिए तथा उन पर कर लगाया जाना चाहिए।

इन कदमों से शिक्षा क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आएगा, जैसा कि बैंकिंग, बीमा, नागरिक उड्डयन और दूरसंचार क्षेत्रों में हुआ है। बहुप्रतीक्षित और बहुआयामी NEP-2020 तभी लागू हो सकता है जब हम इस संप्रभु सत्य को स्वीकार करें कि 'आदर्श अर्थव्यवस्था एक आदर्श समाज का स्तंभ है।'



भारत की शिक्षा प्रणाली को ठीक करने की जरूरत है। क्या स्कूल वाउचर हो सकते हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना देश में एक बड़ी चुनौती है।



श्रीमती अपेक्षा वार्षेय
सलाहकार, यूएनडीपी

भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में एक लोकप्रिय कहावत है। "आपको स्कूल में सब कुछ मिलेगा - किताबें, वर्दी, स्कूल बैग, जूते और भोजन", एक शिक्षक छात्र के माता-पिता से कहता है। "और शिक्षा?" माता पिता पूछते हैं। "ओह, आप उसके लिए अपने बच्चे का ट्यूशन में दाखिला करा सकते हैं।" यह दुर्भाग्य से, इस बात का सटीक वर्णन है कि देश को 76.72 प्रतिशत साक्षरता दर की ओर ले जाने के लिए दशकों से एक साथ शिक्षा - भारत में कैसे काम करती है।

लेकिन साक्षरता अपने आप में बहुत कम मायने रखती है जब देश में सीखने के चौकाने वाले परिणाम खराब होते हैं।

गैर-सरकारी संगठन 2018 प्रथम की वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट (ASER) के अनुसार, ग्रामीण भारत के 596 जिलों में 95 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। लेकिन उनमें से, ग्रेड 3 में केवल 27.2 प्रतिशत अक्षर, शब्द, ग्रेड 1 के स्तर पर एक साधारण पैराग्राफ या कठिनाई के ग्रेड 2 के स्तर पर एक कहानी पढ़ सकते हैं। उनके पास बुनियादी अंकगणितीय कौशल का भी अभाव है; कक्षा 8 के सभी बच्चों में से केवल 44 प्रतिशत ही सरल विभाजन योगों को सही ढंग से हल करने में सक्षम हैं।

जब आंकड़ों को परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है तो आंकड़े और भी खतरनाक होते हैं: सोचें कि बच्चों में प्रतिदिन काम न कर पाने जैसे चिकित्सीय नुस्खे पढ़ना या बुनियादी गणना करना। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत की सार्वभौमिक नामांकन की उपलब्धि के बावजूद, किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल करने के बजाय, अधिक जवाबदेही की जरूरत है।

निस्संदेह, उत्तम शिक्षा का पहला कदम है परंतु इसे मौलिक अधिकार प्रदान करना उस समय अत्यंत कठिन कार्य सिद्ध हुआ है, जब आप भारत

में पब्लिक स्कूल चलाने वाली अक्षम नौकरशाही, तीन संघीय, राज्य और केन्द्र स्तर, आकलन मॉडल की कमी और शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के (डिजाइन और कार्यान्वयन में विलंब) तथा शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम (जिसमें निजी स्कूलों को वंचित छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया है) का प्रावधान रखते हैं।

दिल्ली में एक थिंक टैंक, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी (सीसीएस) का मानना है कि भारतीय शिक्षा में एक बहुत जरूरी हस्तक्षेप स्कूल वाउचर का विश्व स्तर पर स्वीकृत समाधान है।

वर्ष 2007 में, CCS(सीसीएस) ने भारत का पहला वाउचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें दिल्ली की 68 स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के 408 छात्रों को तीन साल या उससे कम समय के लिए लगभग ₹3,600 (~ US \$50) के स्कूल वाउचर दिए गए। थिंक टैंक और अन्य स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित, कार्यक्रम ने माता-पिता और बच्चों को वाउचर का उपयोग करने और पड़ोस के निजी स्कूल में नामांकन करने की अनुमति दी। जब बच्चे, जो पहले सरकारी स्कूलों में जाते थे, का एक साल बाद परिणामों के लिए परीक्षण किया गया, तो सीसीएस ने पाया कि उन्होंने निजी या सरकारी दोनों स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में सभी ग्रेड में अंग्रेजी, गणित और हिंदी में बेहतर प्रदर्शन किया। तब से, सीसीएस और अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब जैसे अन्य संगठनों ने पूरे भारत में इसी तरह के कार्यक्रम लागू किए हैं।

स्कूल की पसंद

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का मानना था कि स्कूल को फंड करने के बजाय, सरकार को छात्रों को फंड देना चाहिए। फंड छात्रों (और उनके परिवारों) को अनजाने में पड़ोस के पब्लिक स्कूल में शामिल होने के बजाय एक स्कूल चुनने की अनुमति देगा। यह सार्वजनिक और निजी स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर अधिक उत्कृष्टता और दक्षता भी लाएगा। अब तक, चिली ने वाउचरीकृत प्रणाली का पालन किया है लेकिन इसकी प्रभावकारिता के बारे में मिश्रित प्रमाण हैं।

सीसीएस के वरिष्ठ सहयोगी एलस्टन डिसूजा ने इस आधार पर कहा, "स्कूल सरकार के प्रति जवाबदेह हैं लेकिन सरकार उनकी निगरानी और मूल्यांकन का घटिया काम करती है," उन्होंने री: सेट को बताया। "इसका मतलब है कि स्कूलों [और शिक्षकों] को शिक्षा की गुणवत्ता की परवाह किए बिना भुगतान मिलता है।"

हालांकि वाउचर के साथ, "माता-पिता स्कूल को भुगतान करते हैं और इसलिए, वे उपभोक्ता हैं जो स्कूल को जवाबदेह ठहरा सकते हैं," डिसूजा



Children receiving school vouchers from child rights organizations.

ने कहा। एक कदम पीछे हटना और यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में अपने बच्चों को सरकारी (सार्वजनिक) स्कूलों में कौन भेजता है। सीसीएस में शोध प्रबंधक क्रतिका शाह, जिन्होंने स्कूल वाउचर की खूबियों की खोज करने वाली रिपोर्टों पर काम किया है, ने कहा, "यह सबसे गरीब है, जिसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।" लेकिन यह वही स्कूल हैं जिनमें भारत के सबसे वंचित लोग जाते हैं, जिनमें न केवल शिक्षकों की कमी है, बल्कि वे ढहते बुनियादी ढांचे और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की पूर्ण कमी के तहत भी काम करते हैं।

टीच फॉर इंडिया के सीईओ शाहीन मिस्त्री, टीच फॉर ऑल नेटवर्क के एक गैर-लाभकारी हिस्से के अनुसार, "ये पड़ोस के स्कूल हैं," वाउचर सिस्टम पर दबाव बना सकता है। और उन्हें "गुणवत्ता में सुधार करने या नामांकन खोने के लिए" मजबूर करते हैं, उसने रे: सेट को बताया।

तेजी से सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हो रहा है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 30.9 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित हैं। वाउचर सिस्टम के समर्थकों का तर्क है कि अगर लोग निजी स्कूलों को पसंद करते हैं और अगर सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, तो उससे सार्वजनिक संसाधनों का अभाव क्यों होना चाहिए?

Pratham के सह-संस्थापक फरीदा लांबे ने रे:सेट को बताया, "यह सच नहीं है कि सभी सरकारी स्कूल खराब प्रदर्शन कर रहे हैं।" "कुछ भारत में बजट या मिड-रेंज निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।" नीति कार्यान्वयन संगठन, इंडस एक्शन के सीईओ तरुण चेरुकुरी सहित अन्य लोग सोचते हैं कि "शिक्षा को सार्वजनिक रूप से अच्छा रहना चाहिए।" "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा," चेरुकुरी ने एक साक्षात्कार में कहा, अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है जैसे "स्कूल प्रबंधन समितियों को मजबूत करना या माता-पिता को स्कूल की गुणवत्ता पर विस्तृत और मान्य जानकारी प्रदान करना।"

सुझाव उत्कृष्ट हैं, लेकिन समस्या यह है कि इनमें से किसी भी हस्तक्षेप ने अब तक काम नहीं किया है, जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.845 प्रतिशत पैसा पब्लिक स्कूलों में प्रवाहित होता रहा है। "सार्वजनिक वित्त के दृष्टिकोण से भी," गीता गांधी किंगडन के शोध का हवाला देते हुए डिस्जुजा ने कहा, "निजी स्कूल सरकार की तुलना में प्रति छात्र तीन से आठ गुना कम खर्च करते हैं।"

शाह के लिए, हालांकि, तर्क सार्वजनिक या निजी स्कूलों के बीच नहीं है, बल्कि उन स्कूलों के बीच है जो प्रदर्शन करते हैं और जो नहीं करते हैं। "सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूल सह-अस्तित्व में हो सकते हैं लेकिन अस्तित्व का आधार प्रदर्शन और माता-पिता की प्राथमिकता होनी चाहिए।" इसका मतलब यह है कि यदि वाउचर मॉडल सक्षम किया गया था, तो बच्चा और माता-पिता किसी भी सरकारी या निजी स्कूल को चुन सकते थे। लेकिन सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले पब्लिक स्कूल के बजाय, यह उन छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगा जो उस स्कूल में दाखिला लेने का निर्णय लेते हैं। यदि स्कूल, सार्वजनिक या निजी, छात्रों को आकर्षित करने में विफल रहता है, तो उसे बंद करना संभव होगा और इस प्रकार स्कूल प्रशासन पर उनके कार्य को एक साथ लाने की जिम्मेदारी होगी।

और यहीं पर राजनीतिक प्रभाव के साथ कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है। यदि स्कूल को छात्रों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, न कि सरकार



A school principal addresses the families participating in CCS' pilot program.

द्वारा, तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मिलने वाले उच्च वेतन को खतरा होगा। डिस्जुजा ने कहा, "शिक्षक संघ - जो जनगणना, मतदान सूची और दूरदराज के इलाकों में प्रचार में मदद करता है - राजनेता के लिए मूल्यवान है।" "वाउचर का मतलब है कि शिक्षकों को न केवल कड़ी मेहनत करनी होगी, बल्कि वेतन में कटौती का भी अनुभव हो सकता है। और यह इसे राजनीतिक रूप से अक्षम्य बनाता है।"

राजनीतिक इच्छाशक्ति के अलावा, लाम्बे और मिस्त्री वाउचर के कार्यान्वयन के बारे में व्यावहारिक चिंताओं को उठाते हैं। "क्या प्रवेश उचित होगा?" मिस्त्री पूछते हैं। "क्या बच्चों को अकादमिक रूप से पकड़ने के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है? क्या उनका समर्थन किया जाएगा ताकि वे भेदभाव का अनुभव न करें और ताकि वे सामाजिक रूप से एकीकृत हो सकें?"

सीसीएस के पायलट प्रोजेक्ट के बाद, 94% माता-पिता ने जवाब दिया कि वे स्कूल से संतुष्ट हैं, लेकिन सामाजिक एकीकरण के सवाल भारत जैसे देश में विशेष महत्व रखते हैं जहाँ आय असमानता और जातिगत भेदभाव व्यापक है। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के छात्रों को कक्षा में कितने प्रभावी ढंग से आत्मसात किया जाता है।

प्रणाली के डिजाइन के बारे में अन्य प्रश्न जैसे कि निजी स्कूलों में न केवल भाग लेने के लिए प्रोत्साहन है, बल्कि सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को नामांकित करने के इच्छुक भी हैं। शाह इनमें से कई से सहमत हैं और उनमें से कुछ जोड़ते हैं, "क्या राज्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्र के खाते में पैसे भेजने का फैसला करेगा? क्या इसमें इतने बड़े पैमाने पर डीबीटी करने की क्षमता है? क्या यह अपरिहार्य रूप से बहिष्कृत लोगों के लिए समायोजन करेगा? यह चांदी की गोली नहीं है," उसने निष्कर्ष निकाला, "हमें कई सुधारों की आवश्यकता है।"

लेकिन सभी बातों पर विचार किया गया, वाउचर के माध्यम से वित्त पोषण के मार्ग को बदलना जो छात्र, स्कूल और राज्य के बीच संबंधों को बदल देता है, अधिक परीक्षण और अन्वेषण के योग्य है।

यह लेख 5 अप्रैल 2016 को रीसेट फेस्ट में प्रकाशित हुआ था।

कर्नाटक का 'निवारक प्रोटोकॉल' सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में कैसे मदद कर सकता है?



श्रीमती कात्यायनी चामराज
कार्यकारी ट्रस्टी, CIVIC बैंगलोर

यह एक बहुत, बहुत अच्छी याचिका है," भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2018 में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की एक पंजीकृत संस्था अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था।

29 जनवरी, 2018 को इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, समाज ने देश में छह से 14 साल के बीच के 3.5 करोड़ गरीब बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार को लागू करने की माँग की थी, जो देश में स्कूल से बाहर थे। नवंबर 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के एक और सीजेआई ने इसी मामले की सुनवाई की। हालाँकि, उन्होंने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि, "चमत्कार की उम्मीद मत करो। भारत एक विशाल, देश है। प्राथमिकताएं कई हैं और निश्चित रूप से, शिक्षा प्राथमिकताओं में से एक है।"

तो इन 3.5 करोड़ बच्चों के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या हुआ, जिन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था? बी.आर अंबेडकर के अनुसार, अनुच्छेद 32 "संविधान का दिल और आत्मा है" और इसके माध्यम से दिए गए अधिकारों का प्रयोग हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा।

1970 के दशक से पहले, केवल प्रभावित पक्षों के पास मामला दर्ज करने का अधिकार था, जिसका अर्थ है कि शिक्षा के अधिकार से वंचित 3.5 करोड़ बच्चों में से कोई भी अदालत में जा सकता था। हालांकि, आपातकाल के बाद यह सिद्धांत बदल गया।

कानूनी विशेषज्ञों का मत था कि जनहित याचिका केवल प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर करने की आवश्यकता नहीं है जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, बल्कि इसे किसी के द्वारा भी जनता के लाभ के लिए दायर किया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, विशेषज्ञों ने कहा कि या तो सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले सकता है और खुद को आगे बढ़ा सकता है या सार्वजनिक लाभ के लिए किसी व्यक्ति की ओर से एक याचिका पर सुनवाई कर सकता है। यह स्पष्ट है कि स्कूल न जाने वाले 3.5 करोड़ बच्चों में से किसी के पास भी उनके शिक्षा के अधिकार की बहाली के लिए अदालत जाने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं होंगे। इसलिए, एक जन-उत्साही संगठन ने उनकी ओर से अदालत का रुख किया।

हालांकि, परिणाम निस्संदेह एक त्रासदी थी।

इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि नवीनतम अनुमानों ने स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या को और भी अधिक बढ़ा दिया है। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) प्लस की 2020-21 की रिपोर्ट से पता चलता है कि दी गई अवधि कक्षा 1 से 5 तक का शुद्ध नामांकन अनुपात 92.7% था और कक्षा 6 से 8 के लिए यह 74.1% था।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 6 से 11 वर्ष की आयु के लगभग 7% बच्चे और 12 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 25% बच्चे स्कूल से बाहर हैं और उन्होंने अनिवार्य शिक्षा के आठ वर्ष भी पूरे नहीं किए होंगे। इसका मतलब है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 6 से 14



वर्ष की आयु के अनिवार्य स्कूल के लगभग 23.3 करोड़ बच्चों में से लगभग 5.5 करोड़ बच्चे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं हैं।

2002 में, 86 वें संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा बना दिया और 2009 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया।

लेकिन सवाल यह है कि अनुच्छेद 21ए और आरटीई अधिनियम, 2009 के बावजूद 3.5 करोड़ बच्चे, या नवीनतम यूडीआईएसई के आंकड़ों के अनुसार 5.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर क्यों रहते हैं?

ऐसा प्रतीत होता है कि 10 साल की अवधि के भीतर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने पर संविधान के पहले के अनुच्छेद 45 का उन्नयन, जो कि राज्य की नीति का केवल एक निर्देशक सिद्धांत था, एक मौलिक अधिकार की स्थिति में, इसे एक अदालत के तहत न्यायसंगत बना दिया। , राज्य के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं लाया है, यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा अनिवार्य रूप से शिक्षित है।

आरटीई अधिनियम की धारा 4 में बच्चे के 'अनिवार्य प्रतिधारण' के 'निवारक' दृष्टिकोण के बजाय 'पुनर्वास' का 'उपचारात्मक' दृष्टिकोण है। यह इस प्रकार पढ़ता है: "उन बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश नहीं दिया है, या जिन्होंने पूरा नहीं किया है: जहाँ छह साल से अधिक उम्र के बच्चे को किसी भी स्कूल में भर्ती नहीं किया गया है या भर्ती कराया गया है, वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका है, तो उसे उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।"

यह (Section) अनुभाग आगे "बशर्ते कि जहाँ एक बच्चे को उसकी उम्र के लिए उपयुक्त कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, तो उसे दूसरों के बराबर होने के लिए, इस तरह से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा, और ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो निर्धारित की जाए।"

उपरोक्त प्रावधान यह मानता है कि एक बच्चा लंबे समय से स्कूल से बाहर है और उसे ब्रिज कोर्स की आवश्यकता होगी। किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए आरटीई अधिनियम में कोई वैधानिक प्रावधान/प्रोटोकॉल नहीं है।

आरटीई अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान के आधार पर, कर्नाटक में 'ड्रॉप-आउट' की परिभाषा थी: "कोई भी बच्चा किसी भी शैक्षणिक वर्ष (चिकित्सा आधार को छोड़कर) में 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है और खुद को पेश नहीं करता है उसके बाद स्कूल जाना।"

अधिकांश अन्य राज्य भी इसी तरह से ड्रॉप-आउट को परिभाषित करते हैं। 'ड्रॉप-आउट' की ऐसी परिभाषा के साथ, एक बच्चा महीनों तक स्कूल से बाहर रह सकता है, साथ ही अनुच्छेद 21 ए के तहत उसके जीवन के निहित अधिकार का उल्लंघन करता है, और साथ ही उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसे बच्चों का लंबे समय तक ड्रॉप-आउट और बाल मजदूर बनने के बाद पुनर्वास किया जा रहा है।

टेंट स्कूल, ब्रिज स्कूल, गैर-औपचारिक स्कूल, फ्लेक्सी-स्कूल आदि, शिक्षा में गैर-भेदभाव पर यूनेस्को के कन्वेंशन के उल्लंघन में उनके पुनर्वास के लिए समानांतर धाराओं के रूप में जारी हैं।

एक निवारक या एक पुनर्वास दृष्टिकोण?

"हालांकि अधिकांश स्कूल मई या जून में अपने शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत करते हैं, शिक्षा मंत्रालय (2009 के एमएचआरडी दिशानिर्देश) की सिफारिश कर रहा है, और राज्य भी कई महीनों बाद सर्वेक्षण कर रहे हैं, ज्यादातर दिसंबर और जनवरी में ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है या जो शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद शामिल नहीं हुए हैं।

सर्वेक्षण महीनों बाद स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान करते हैं, उन्हें गर्मियों के दौरान उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रमों में डालते हैं और अगले शैक्षणिक वर्ष में उन्हें औपचारिक स्कूल में वापस रखते हैं।

हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पहचाने गए स्कूल से बाहर के सभी बच्चे पुनर्वास कार्यक्रमों से गुजरेंगे और पुनर्वासित बच्चे फिर से पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे (अध्ययन के अनुसार उनमें से 50% से अधिक फिर से स्कूल छोड़ देते हैं)।



आरटीई अधिनियम में सबसे स्पष्ट कमी यह है कि सरकार में किसी को भी ऐसे बच्चे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है जो इतनी लंबी अवधि के लिए स्कूल से बाहर हैं, हालांकि मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। एक कानून जो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता है और इसके उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं देता है, उसे एक प्रभावी कानून नहीं कहा जा सकता है।

कर्नाटक के एक पूर्व श्रम मंत्री ने ब्रिजिंग कार्यक्रमों के संचालन के 'उपचारात्मक' दृष्टिकोण की निरर्थकता को परोक्ष रूप से उजागर किया। राज्य की बाल श्रम कार्य योजना के तहत 12 साल की अवधि में केवल 1.08 लाख बाल मजदूरों को मुख्यधारा में लाया गया। इस कार्यक्रम के तहत पुनर्वासित होने से पहले बच्चे 14 वर्ष की आयु पार कर चुके होंगे। यह एक 'उपचारात्मक' दृष्टिकोण के माध्यम से किसी भी समय दिए गए लाखों स्कूली बच्चों के पुनर्वास की असंभवता को इंगित करता है। 'उपचारात्मक' ब्रिजिंग कार्यक्रम एक करछुल के साथ पानी को बाहर निकालने जैसा है जबकि नाव रिसना के माध्यम से भर रही है। जब तक 'रिसाव' को पहले लाक्षणिक रूप से बंद नहीं किया जाता है, तब तक ब्रिजिंग कार्यक्रमों की कोई भी राशि व्यर्थ होगी।

जून 2012 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बहुसंख्य माता-पिता और बच्चों ने आर्थिक मजबूरियों को बच्चों के स्कूल छोड़ने का कारण बताया है। हालांकि, RTI अधिनियम केवल धारा 8 (सी) और 9 (सी) के तहत कहता है कि उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण "यह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और उन्हें रोका नहीं जाता है। किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने और पूरा करने से।" लेकिन आरटीई अधिनियम और अधिकांश राज्य नियम यह नहीं कहते कि यह कैसे किया जाना है।

कर्नाटक के आरटीई नियम, 2012 के अनुसार, नियम 4 (9) केवल कहता है: "सीपीआई (सार्वजनिक निर्देश आयुक्त) या स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की स्कूल तक पहुंच सामाजिक और

सांस्कृतिक कारकों के कारण बाधित न हो।"

हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2018 में देश भर में स्कूल ना जाने वाले 3.5 करोड़ बच्चों के मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत स्वतः संज्ञान लेने में विफल रहा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह खुशी की बात है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक कदम उठाया था। इन सभी बच्चों को राज्य में स्कूल वापस लाने के लिए 2013 में ही (WP 15768/2013) स्वतः स्वयं से प्रेरणा ली थी।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीएच वाघेला और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की एक पीठ ने कर्नाटक सरकार को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था: "31 मार्च, 2013 को द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अवलोकन पर, जिसका शीर्षक द ग्लिच डैट डॉग आरटीई कार्यान्वयन है, जिसमें लगभग 54,000 छात्र हैं। कर्नाटक में अभी भी स्कूल से बाहर हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों के मौलिक अधिकार के कथित उल्लंघन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेना उचित समझा जाता है।"

कर्नाटक की इस अग्रणी पहल के माध्यम से अभी भी चल रही स्वतः प्रेरणा जनहित याचिका उपचारात्मक, पुनर्वास दृष्टिकोण से दूर हो गई है और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए अपने आरटीई नियमों में एक 'निवारक प्रोटोकॉल' पेश किया है और यह सुनिश्चित किया है कि मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उनका मौलिक अधिकार सुनिश्चित हो। शिक्षा लगातार सुनिश्चित की जाती है। यह पुनर्वास ब्रिजिंग कार्यक्रमों को अनावश्यक बनाता है। अधिकांश अन्य देशों के अनिवार्य शिक्षा कानून इस तरह के निवारक दृष्टिकोण को अनिवार्य करते हैं।

जनहित याचिका ने 'ड्रॉप-आउट' की परिभाषा में बदलाव लाया। ऊपर उल्लिखित 'ड्रॉप-आउट' की पहले की परिभाषा को संशोधित किया गया था और इसे "सात दिनों की अनुपस्थिति वाले बच्चे" के रूप में लाया गया था, ताकि बच्चे को लंबे समय तक ड्रॉप-आउट बनने से रोकने के लिए कार्रवाई तुरंत शुरू की जा सके जो बच्चे के बाहर निकलने के पहले लक्षण हैं।



इसके बाद, नियम 6ए से 6डी, बच्चे को वापस स्कूल लाने के लिए एक निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल की वर्तनी को नियम 6 में जोड़ा गया।

संक्षेप में, संशोधित नियम निम्नलिखित कहते हैं:

आरटीई अधिनियम में कमी को दूर करने के लिए, जो यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट सरकारी अधिकारी पर कोई जवाबदेही तय नहीं करता है कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जाता है, क्लस्टर स्तर पर शिक्षा समन्वयकों (ईसीओ) को कर्नाटक द्वारा उपस्थिति अधिकारियों के रूप में नामित किया गया था ताकि बच्चे के सात दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू की जा सके। एक बच्चे के शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए राज्य के कर्तव्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा के भीतर स्कूल छोड़ना और हर बच्चे को स्कूल वापस लाना।

आरटीई अधिनियम में कमी को दूर करने के लिए, जो यह रेखांकित करने में विफल रहता है कि एक 'कमजोर' बच्चे, जो एक वंचित वर्ग या कमजोर वर्ग से संबंधित हो सकता है, द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक बाधाओं को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए, प्रोटोकॉल मूल को संबोधित करता है एक बच्चे के निम्नलिखित तरीके से बाहर निकलने का कारण। यदि माता-पिता द्वारा अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मनाना विफल हो जाता है, तो उपस्थिति अधिकारियों को इन बच्चों और उनके माता-पिता/अभिभावकों को जिला स्तर पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित बाल कल्याण समितियों ((सीडब्ल्यूसी)) के समक्ष लाना होगा।

(सीडब्ल्यूसी) को बच्चे के स्कूल छोड़ने के कारणों की जाँच करनी होती है और विभिन्न विभागों से उपलब्ध किसी भी आवश्यक सहायता/लाभ को मिलाकर परिवार को उपयुक्त सहायता प्रदान करनी होती है।

यदि कोई बच्चा माता-पिता से उपयुक्त सहायता प्राप्त करने के बाद भी स्कूल नहीं आता है, तो (सीडब्ल्यूसी) को किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चे को 'देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे' के रूप में लेना होगा और उसे एक मुफ्त सरकारी आवासीय स्कूल में प्रवेश देना होगा। ; या उसे एक समय-सीमा के भीतर शिक्षा के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त संस्थान, पालक गृह आदि में भेज दें।

उपरोक्त प्रोटोकॉल 1997 में न्यायमूर्ति वीपी मोहन कुमार द्वारा ए. श्रीराम बाबू बनाम मुख्य सचिव [6 जून, 1997 को 1997 के डब्ल्यूपी 1351 में] के एक पूर्व कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप हैं। इस फैसले में कहा गया है: "... संप्रभु, यानी राज्य में निहित नाबालिग की संरक्षकता संप्रभु ने माता-पिता को संरक्षकता सौंपी थी। यदि वे विफल हो जाते हैं, तो संप्रभु अधिकार फिर से शुरू कर सकते हैं। "

अब तक, यह निर्णय है कि राज्य को उन नाबालिगों का प्रभार लेना चाहिए जिन्हें उनके माता-पिता द्वारा अधिकारों से वंचित किया गया है, कभी भी लागू नहीं किया गया था। WP 15768/2013 में अदालत के हस्तक्षेप ने राज्य की जिम्मेदारी को मजबूत करते हुए इस फैसले को लागू किया।

एक अनोखा मॉडल

कर्नाटक ने प्रवासी कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए एक नीति भी तैयार की है - जो देश में प्रथम में से एक है। स्कूल न जाने वाले बच्चों पर राज्य का आरटीई प्रोटोकॉल भी देश में पहला है। इसने बाल अधिकारों पर

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरसी) के निम्नलिखित लेखों के प्रावधानों को अपने नियमों में शामिल किया है:

अनुच्छेद 28: 'सभी बच्चों के लिए समान अवसर के आधार पर' निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा है। इसका मतलब है कि एक बच्चे को औपचारिक स्कूल में जाना पड़ता है, और बाल मजदूरों को समायोजित करने के लिए शाम की कक्षाएँ, फ्लेक्सी-स्कूल और टेंट स्कूल स्वीकार्य नहीं हैं।

अनुच्छेद 18(2) और 19: जब माता-पिता बच्चों के अधिकारों को प्रदान करने में असमर्थ या अनिच्छुक हों, तो राज्य को बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी सहायता करनी चाहिए।

अनुच्छेद 9(1): लागू कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार, बच्चे को उसके माता-पिता से अलग किया जा सकता है, जब बच्चे के सर्वोत्तम हितों के लिए ऐसा अलगाव आवश्यक हो।

स्कूल न जाने वाले बच्चों पर कर्नाटक के आरटीई नियमों में उपरोक्त यूएनसीआरसी प्रावधानों को शामिल करना पूरे देश में अद्वितीय है। चूंकि किसी भी राज्य में एक उच्च न्यायालय का फैसला अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है, इसलिए WP 15768/2013 के माध्यम से किए गए परिवर्तन CIVIC बैंगलोर द्वारा नई शिक्षा नीति (NEP) के माध्यम से भारत भर में अपनाने की सिफारिशों के रूप में प्रस्तुत किए गए थे।

हालांकि, इस मामले पर शिक्षा सचिवालय या एनईपी का मसौदा तैयार करने वाली समिति की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। यदि इसे एनईपी द्वारा अपनाया गया होता और संशोधनों के माध्यम से केंद्रीय आरटीई अधिनियम में बनाया जाता, तो इसे पूरे देश में दोहराया और बढ़ाया जा सकता था, लगभग 5.5 करोड़ बच्चों को देश में स्कूल छोड़कर मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में बढ़ाया गया।

कर्नाटक के आरटीई नियमों के नियम 6 में किए गए संशोधनों के माध्यम से सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए 'निवारक प्रोटोकॉल' का विवरण नीचे दिया गया है





- नियम 6ए (1): उपस्थिति प्राधिकरण ((एए)) (सरकारी अधिकारी) के रूप में नामित प्रत्येक क्लस्टर में शिक्षा समन्वयक (ईसीओ) को 100% यूईई सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होना चाहिए।
- नियम 6ए (2): स्कूल खुलने से एक महीने पहले वीईआर/डब्ल्यूईआर तैयार करना। उपस्थिति प्राधिकरण उन सभी अभिभावकों को उपस्थिति सूचना जारी करेगा जिनके बच्चे स्कूल आने के पात्र हैं।
- नियम 6बी(1): यदि कोई बच्चा 7 दिनों के लिए स्कूल में शामिल होने या आने में विफल रहता है, तो अगले 3 दिनों के भीतर, (एचएम) पूछताछ करने के लिए और यदि गैर-उपस्थिति के लिए कोई उचित बहाना मौजूद नहीं है, तो अगले तीन दिनों के भीतर (एए) को सूचित करें।
- नियम 6बी(2) - उपस्थिति सूचना: (एए) पूछताछ करने के लिए और यदि गैर-उपस्थिति के लिए कोई उचित बहाना मौजूद नहीं है, तो माता-पिता को उपस्थिति नोटिस जारी करने और स्वीकृति लेने के लिए।
- नियम 6सी: गैर-उपस्थिति के लिए उचित बहाना - बच्चे को कहीं और नामांकित किया गया है, या आपदाएं, दंगे, आदि बच्चे को स्कूल आने से रोकते हैं।
- नियम 6डी(1): अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय - (एए) को ग्राम पंचायत सदस्यों/शिक्षा, स्कूल विकास और निगरानी समितियों, गैर सरकारी संगठनों पर ग्राम पंचायत सदस्यों/नगरपालिका स्थायी समितियों के साथ मिलकर जाँच करने और माता-पिता को मनाने के लिए काम करना है।

- नियम 6डी (2): उपस्थिति आदेश - यदि बच्चा माता-पिता (दो सप्ताह में निर्धारित समय-सीमा) के अनुनय-विनय के बाद भी स्कूल आने में विफल रहता है, तो (एए) माता-पिता को जेजे अधिनियम के तहत जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए उपस्थिति आदेश जारी करता है। विशिष्ट तिथि पर।
- नियम 6डी(3): इन बच्चों और उनके माता-पिता/अभिभावकों को बाल कल्याण समितियों ((सीडब्ल्यूसी)) के समक्ष लाने के लिए यदि आवश्यक हो तो (एए) एसजेपीयू की मदद लें।
- नियम 6डी(4): (सीडब्ल्यूसी) माता-पिता से पूछताछ करेगी और बच्चे के न आने के कारणों का पता लगाएगी।
- नियम 6डी(5): (सीडब्ल्यूसी) पात्रता मानदंड के आधार पर सशर्त छात्रवृत्ति की मंजूरी देकर परिवार को उपयुक्त सहायता प्रदान करता है और / या परिवार पर विभिन्न विभागों के लाभों को परिवर्तित करता है और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है।
- नियम 6डी(6): कम करने वाले कारक जिनके तहत माता-पिता को सहायता दी जानी है, उन्हें (सीडब्ल्यूसी) को परिचालित किया जाना है।
- नियम 6डी(8): यदि बच्चा अभी भी स्कूल नहीं आता है, तो (सीडब्ल्यूसी) बच्चे का प्रभार लेने के लिए और उसे मुफ्त सरकारी छात्रावास/आवासीय स्कूल में प्रवेश देने के लिए (मुफ्त छात्रावासों में सीटें खाली हैं); या उन्हें जेजे एक्ट के तहत शेल्टर होम, फिट इंस्टीट्यूशन, फोस्टर होम आदि में भेजना।

नोट: मामला WP 15768/2013 कर्नाटक उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.एच. वाघेला द्वारा 1 अप्रैल 2013 को स्वतः संज्ञान लिया गया था। लेखक ने इस मामले में अपना पक्ष रखा था। उनके सुझावों को सुनने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-विभागीय समन्वय समिति का गठन किया गया था।

इन संशोधित नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिए मामला अभी भी चल रहा है कि कर्नाटक में सभी बच्चे स्कूल में हैं।

लेखक CIVIC बैंगलोर के कार्यकारी ट्रस्टी हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्वतः संज्ञान WP 15768/2013 में एक पार्टी-इन-पर्सन हैं।

यह लेख पहली बार 24 अक्टूबर, 2022 को द वायर पर प्रकाशित हुआ था।

कंबोडिया के फ्लोटिंग स्कूल



NISA प्रतिनिधिमंडल टीम को नवंबर 2022 में एक फ्लोटिंग स्कूल का दौरा करने का अवसर मिला, वियतनाम में इस तरह का पहला, एक कक्षा और आधुनिक उपकरण के साथ, जिसे मेकांग डेल्टा विन्ह लांग प्रांत में परिचालन में लाया गया है। परियोजना बहुत फायदेमंद है मेकांग डेल्टा में दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों के लिए। स्कूलों को मोबाइल और विभिन्न स्थानों तक पहुंच योग्य बनाकर, इसने आधुनिक तकनीक तक पहुंच में सुधार किया।

कैन थो सिटी में, स्वयंसेवकों के शिक्षकों का एक समूह फ्लोटिंग राफ्ट के शीर्ष से मुफ्त अंग्रेजी कक्षाएँ प्रदान कर रहा है, जिससे सभी उम्र और सामाजिक आर्थिक स्तर के स्थानीय लोगों को आगंतुकों के साथ अंग्रेजी में बातचीत करने का मौका मिलता है। 20 से अधिक छात्रों को मुफ्त-ट्यूशन कार्यक्रम में देशी वक्ताओं की मदद से अपनी अंग्रेजी क्षमताओं में सुधार करने का अवसर दिया जाता है, जो सप्ताह में दो बार कोन सोन (सोन आइलेट) के ऊपर एक मछली पालन बेड़ा पर मिलता है, जो बिन्ह थ्यू के तट पर है। जिला, कैन थो सिटी।

NISA के अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा कहते हैं, "कक्षा में हर बच्चे की वहाँ होने की अलग प्रेरणा होती है।" अन्य डिलीवरी ड्राइवर और नाव कप्तान हैं, जबकि कुछ बाग मालिक हैं जो अपनी स्थापना को एक पर्यटक आकर्षण के रूप में बाजार में देखना चाहते हैं।

सभी के लिए एक फ्लोटिंग क्लास

एक बार प्राध्यापकों और छात्रों के सैम्पल्स में तैरने वाली कक्षा में आने के बाद प्रत्येक कक्षा छात्रों और उनके मेजबानों के बीच एक साधारण हाथ मिलाने के साथ शुरू होती है।

छात्र अब बिना किसी परेशानी के अपना और अपने परिवार का परिचय दे सकते हैं। जिस किसी के पास खाली समय है, उसका भाग लेने के लिए स्वागत है। शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि प्रत्येक छात्र को उस गति से पढ़ाया जाए जिसका वे अनुसरण कर सकते हैं और यह कि कक्षाएँ उनके छात्रों के विभिन्न कौशलों से अच्छी तरह परिचित होने के बावजूद उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल हैं।

विद्यार्थियों के लिए कुर्सियों को 'यू' फॉर्म में 50 वर्ग मीटर की छत पर व्यवस्थित किया जाता है जहाँ कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन सभी छात्रों के लिए, अपने शिक्षक को देखना संभव

बनाता है और छात्र से छात्र सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही वहाँ आकर खुश हैं। शिक्षक अपने काम पर बहुत गर्व महसूस करते हैं और बेहतर अंग्रेजी संचार के माध्यम से स्थानीय पर्यटन सेवाओं के सुधार में योगदान देने में प्रसन्न हैं।

अधिकांश छात्र—70% से अधिक—अपना परिचय अंग्रेजी में दे सकते हैं और व्यंजनों पर चर्चा कर सकते हैं। अंग्रेजी के प्रति छात्रों का संपर्क बढ़ाने और बोलने में उनकी मदद करने के लिए, शिक्षण दल ने एक ऑनलाइन समुदाय भी स्थापित किया। छात्र ऑनलाइन समूह में प्रश्न पूछकर और शिक्षकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करके जो सीखा है उसका मूल्यांकन करने और भाग लेने में सक्षम होंगे क्योंकि यह अंग्रेजी सत अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता है।

पिछले दस वर्षों में, कंबोडिया की शिक्षा प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के प्रति, देश की संवेदनशीलता के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। कंबोडिया के 11 प्रांतों में 200 से अधिक स्कूल कुछ महीने पहले अचानक आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे उनमें से कई को बंद करना पड़ा था। 170 से अधिक बस्तियाँ, अनुमानित 80,000 लोग तैरते हुए गाँवों में रहते हैं। बच्चों की शिक्षा और डोंगी से तैरते हुए स्कूलों तक जाने में बाधा और भी बुरी है।



पुस्तक समीक्षा, गुड नाइट टिंकू!



प्रदीप कुमार
निदेशक - कार्यक्रम और भागीदारी, भारत, वर्ल्डरीडर



प्रीती नांबियार द्वारा लिखा हुआ, सोनल गोयल और सुमित सखूजा द्वारा चित्रित, और प्रथम बुक्स द्वारा प्रकाशित, 'गुड नाइट, टिंकू!' एक आकर्षक कहानी है जो निशाचर जानवरों की दुनिया में बच्चों की एक झलक देता है, उनकी विशेषताएँ तथा वे क्या करते हैं जब दुनिया सो जाती है।

मंगू के खेत का छोटा सा पिल्ला टिंकू, बिल्कुल भी नहीं सो रहा है। वह रात में बाहर निकलने का फैसला करता है और कई दिलचस्प जानवरों से मिलता है। क्या होता है जब वह इन जानवरों से मिलता है और उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए पूछता है?

शिक्षकों और अभिभावकों के लिए रीडिंग नोट:

माता-पिता के रूप में, क्या आपको कभी-कभी बच्चों को सुलाने में यह मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो आप समझ जाएंगे कि इस प्यारी सी कहानी में टिंकू जो करता है वह क्यों करता है। जानवरों की अपनी दुनिया और भाषा होती है। वे जानवर जो रात के दौरान सक्रिय होते हैं और दिन के दौरान आराम करते हैं, उन्हें निशाचर जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन निशाचर जानवरों में से प्रत्येक की एक अनूठी विशेषता है और इसलिए बच्चों के लिए इन जानवरों और उनके अलग-अलग व्यवहार के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है। बच्चों की मदद करने का एक आकर्षक तरीका जानवरों की इस श्रेणी के बारे में कहानियों के माध्यम से जानें और 'गुड नाइट, टिंकू' बिल्कुल सही कहानी की किताब है।



वर्ल्डरीडर के बुकस्मार्ट प्लेटफॉर्म पर eN-READ से पढ़ने के लिए अपने मोबाइल फोन पर नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।



अपने बच्चों के साथ इस कहानी की किताब को पढ़ें और जब आप पढ़ते हैं तो रुकें और अपने बच्चों से पूछें कि उन्हें क्या लगता है कि ये जानवर रात में क्या कर सकते हैं। इससे निशाचर जानवरों की दुनिया के बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी और उन्हें इन प्रजातियों की अनूठी विशेषताओं के बारे में जानने में मदद मिलेगी। यह अंग्रेजी किताब BookSmart App पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कहानियों में से एक है।

eN-READ NISA गुणवत्ता पहल है जो Worldreader.org द्वारा संचालित है। eN-READ एक स्कूल + होम डिजिटल रीडिंग प्रोग्राम है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NIPUN भारत मिशन से जुड़ा है। eN-READ प्रोग्राम आपके स्कूल को रीडिंग स्कूल में बदल देगा। eN-READ कार्यक्रम में नामांकन के लिए थॉमस एंटनी को thomas@nisaindia.org पर ई-मेल करे।

भार्गवी शर्मा



आगरा में 30 जुलाई, 2022 को ताज होटल और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित NISA ग्रीन स्कूल सम्मेलन में माननीय मुख्य अतिथि श्री एसपी सिंह बघेल, कानून और न्याय राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा एक स्कूली छात्रा भार्गवी शर्मा को डीबीटी वाउचर भेंट किया गया।

“ जब मेरी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने की बात आती है, तो यह मुझे अपने माता-पिता के साथ ऐसा करने की स्वतंत्रता देता है।

- भार्गवी शर्मा

”

शिक्षा में डीबीटी एक वरदान हो सकता है। एक दृष्टिकोण जो एक वाउचर और एक सीसीटी के लाभों को जोड़ता है, जैसे कि बाल श्रम या कम उम्र में शादी को हतोत्साहित करने के लिए स्कूल की फीस के लिए वजीफा देना, स्कूल और घर पर (परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के आधार पर) व्यवहार बदलने के लिए आदर्श है।

राष्ट्रीय और राज्य गतिविधियाँ

15 अक्टूबर, 2022

NISA गुणवत्ता कार्यक्रम BOLO ENGLISH (बोलो इंग्लिश) के संबंध में NISA अंबाला कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। सभी स्कूलों के समन्वयक और शिक्षकों ने भाग लिया और छाल जुड़ाव पर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर NISA के अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा व जिला अध्यक्ष श्री आशुतोष गौर ने विद्यालयों को सम्मानित किया। बोलो इंग्लिश प्रोजेक्ट के निदेशक श्री रोहन जोशी और उनकी टीम ने सल की सुविधा प्रदान की, जिसमें 19 स्कूल शामिल थे।



01

नवंबर 03, 2022

NISA अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने, के-12 शिक्षा में गैर-राज्य अभिनेताओं पर सार्थक और निष्पक्ष नियमों को डिजाइन करने पर पैनल चर्चा को संबोधित किया। इसके बाद सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा 3 नवम्बर को उत्तम नगर में आयोजित यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट शुरू की गई।



02

03

नवंबर (9 - 11), 2022

ब्रेनफीड स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड्स को अब संस्थानों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ET TECHX B2B एक्सपो के अलावा, 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन ने हमें बजट निजी स्कूलों के लिए एक रोमांचक अवसर प्रदान किया। इस प्रतिनिधित्व का उपयोग करके, वे नीति के संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानने के साथ-साथ नए आपूर्तिकर्ताओं और व्यवसायों से जुड़ने में सक्षम हैं।



नवंबर (12-13), 2022

वर्ष का हमारा प्रमुख सम्मेलन, “मंथन” स्कूल लीडरशिप समिट 12-13 नवंबर को उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, जो स्कूली शिक्षा में NEP 2020 के कार्यान्वयन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को एक साथ लाता है।



04

नवंबर (17 - 21), 2022

NISA प्रतिनिधिमंडल टीम ने स्कूलों में उनकी शैक्षणिक प्रथाओं के बारे में जानने के लिए कंबोडिया का दौरा किया।



05

22 नवंबर, 2022

NISA- eN-READ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली के उत्तम नगर में “ओके मॉडल स्कूल” में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में, प्रत्येक स्कूल को एक eN-READ किट प्राप्त होती है, जिसमें 1500+ डिजिटल स्टोरीबुक्स (पहले से ही वितरित) होती हैं। प्रत्येक KG, KG 2, और ग्रेड 1 और 2 के साथ-साथ छात्रों के लिए कार्यपुस्तिकाएँ भी हैं।



06

मीडिया

न्यूज डायरी

नई शिक्षा नीति और पर्यावरण संरक्षण पर हुई चर्चा



रामनगर (नैनीताल)। नई शिक्षा नीति और ग्रीन स्कूल कांसेप्ट दो दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। नई शिक्षा नीति में छात्रों के कौशल सुधार और योग्यता विकास पर और अधिक ध्यान देने पर बल दिया गया। ढिकुली के एक रिजॉर्ट में हुई कार्यशाला में शिक्षा नीति के अलावा पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी चर्चा की गई। ग्रीन स्कूलिंग कांसेप्ट को लेकर वीरेंद्र रावत और डॉ. सुशील गुप्ता ने विद्यालयों की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी पर भी चर्चा की। विशिष्ट अतिथि महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी रहीं। इस मौके पर बसंत बल्लभ भट्ट, अनुज भाटिया, ललित रौतेला, कुलदीप सिंह, प्रदीप सपरा, खगेंद्र भट्ट, ललित जोशी, मनोज बुधलाकोटी, डॉ. प्रसून श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। संवाद

स्कूलों का सुझाव नई शिक्षा नीति के लिए मील का पत्थर साबित होगा: गहतोड़ी

रामनगर। ग्राम ढिकुली क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश के सीबीएससी मान्यता प्राप्त दो सौ से अधिक स्कूलों ने भाग लिया है। कार्यक्रम में वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने पहुँचकर नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों का सुझाव मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति लागू करने वाली है। जिसे देखते हुए ढिकुली के एक रिजॉर्ट में नई शिक्षा नीति को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ कैलाश गहतोड़ी ने दीप जालकर किया। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में देश के कई स्कूलों के अनुभवी शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं।



जो नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर सरकार को बेहतर सुझाव देंगे। बताया कि इन सुझाव को बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया जायेगा जो मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलाउंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष बसन्त बल्लभ भट्ट, नायब सिंह, दिनेश चौधरी, निधि नायर, सुशील गुप्ता, अमित चंद्रा, प्रसून श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। वहीं रामनगर पहुँचने पर कैलाश गहतोड़ी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट, भाजपा नगर अध्यक्ष भावना भट्ट, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, ग्रामीण मंडल महामंत्री हेम चन्द्र जोशी, मीडिया प्रभारी नरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।

नई शिक्षा नीति में छात्रों के कौशल सुधार, योग्यता विकास पर और अधिक ध्यान देने को लेकर हुई चर्चा



रामनगर (मंटा संवाददाता)। अतिरिक्त विद्यालय की प्रबंध समिति कार्यशाला के दूसरे दिन नई शिक्षा नीति विषयक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विद्यालयों व ग्रीन स्कूल कांसेप्ट के ऊपर पेनल में ग्रीन स्कूलिंग कांसेप्ट को लेकर वीरेंद्र चर्चा हुई जिसमें डॉ. अरविंद रावत व डॉ. सुशील गुप्ता ने विद्यालयों की पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों सुदन, डॉ. निधि नायर, डॉ. हरीश के विषय पर भी चर्चा की। तराई चौधरी, डॉ. सुशील गुप्ता, डॉ. प्रमोद, इन्डीपेन्डेंट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष बसंत बल्लभ भट्ट, अनुज भाटिया, ललित रौतेला, कुलदीप सिंह, प्रदीप सपरा, खगेंद्र भट्ट, ललित जोशी, मनोज बुधलाकोटी, डॉ. प्रसून श्रीवास्तव आदि उपलब्ध रहे।

शिक्षाविदों का सुझाव शिक्षा नीति के लिए साबित होगा मील का पत्थर

अमृत विचार, रामनगर

देश भर से आए डेढ़ सौ से अधिक स्कूलों के प्रतिनिधियों की दो दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गहन मंथन किया गया। तराई इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन एवं राष्ट्रीय इंडिपेंडेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में

आयोजित कार्यशाला का मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा कर देश के सभी विद्यालयों में इसे सुचारु रूप से लागू कराना है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों का सुझाव

मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में देश के कई स्कूलों के अनुभवी शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं उनके सुझावों पर सरकार अमल करते हुए शिक्षा नीति को लागू करेगी।

नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, बसन्त बल्लभ भट्ट, आईआईटी दिल्ली के दिनेश चौधरी, नाइब सिंह धारीवाल, निधि नायर, डॉ. प्रानज्योति तेलंगाना, डॉ. सुशील गुप्ता आगरा, डॉ. प्रमोद, डॉ. अमित चंद्रा, वीरेंद्र रावत आदि ने राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। इस दौरान रामनगर से ग्रेट मिशन स्कूल के डॉ. प्रसून श्रीवास्तव, मदर्स ग्लोरी स्कूल से मीना पांथरी के अलावा मनोज बुधलाकोटी, मनोज जोशी मौजूद रहे।



रामनगर में सेमिनार का उद्घाटन करते अतिथि। • अमृत विचार

निसा पदाधिकारी



डॉ कुलभूषण शर्मा
अध्यक्ष



डॉ जे एस परंज्योथि
उपाध्यक्ष (एडवोकेसी)



श्री तुलसी प्रसाद
उपाध्यक्ष (कालिटी)



श्री मार्टिन कैनेडी
उपाध्यक्ष (कानूनी)



डॉ सुशील गुप्ता
उपाध्यक्ष (इनिशिएटिव)



श्री राजेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष (संगठन विकास और भागीदारी)



डॉ प्रेमचंद देशवाल
कोषाध्यक्ष



डॉ पार्थ जे शाह
सचिव



National Independent Schools Alliance

अफोर्डेबल स्कूलिंग कमांडेबल लर्निंग

प्रधान कार्यालय

एच-1ए/1, यूनिट नंबर- 501-503, 5वीं मंजिल
सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301

शाखाएं

हरियाणा

अंबाला
3706, हिल रोड,
एसडी मंदिर के पास,
अंबाला कैट
हरियाणा - 133001

तेलंगाना

हैदराबाद
नगर निगम संख्या
2-3-528/
सी/15/ए/23
अंबरपेट, हैदराबाद
तेलंगाना - 500 013

तमिलनाडु

चेन्नई
6/74, रिदरडन
रोड, वाईएमसीए वेपेरी
कैंपस चेन्नई,
तमिलनाडु - 600084

निसा स्टेट एसोसिएशन के नेता



श्री रामचंद्र रेड्डी

आंध्र प्रदेश प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स
मैनेजमेंट एसोसिएशन
आंध्र प्रदेश



श्री श्रीकांत बाबू कोगंती

इंडिपेंडेंट स्कूल्स मैनेजमेंटस
एसोसिएशन
आंध्र प्रदेश



श्री पंकज दास

ऑल असम प्राइवेट स्कूल्स
एसोसिएशन
असम



श्रीमती नंदिता मिश्रा

व्यक्तिगत विद्यालय
समनायराक्षी
असम



डॉ बीरेंद्र सिंह राय

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
कटिहार
बिहार



श्री दर्विंदर सिंह अरोड़ा

रूरल एजुकेशन वेलफेयर
एसोसिएशन
चंडीगढ़



श्री एच एस मामिक

इंडिपेंडेंट स्कूल्स
एसोसिएशन
चंडीगढ़



श्री राजीव गुप्ता

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल्स
एसोसिएशन
छत्तीसगढ़



डॉ प्रेमचंद देशवाल

प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल्स
एसोसिएशन
दिल्ली



श्री सुरेंद्र कुमार

प्राइमरी स्कूल्स
एसोसिएशन
दिल्ली



डॉ रीना सांगवान

अतुल्या एजुकेशन ट्रस्ट
दिल्ली



श्री अनिल गोयल

साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल
मैनेजमेंट एसोसिएशन
दिल्ली



डॉ लक्ष्य छाबड़िया

अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स
एसोसिएशन
दिल्ली



श्री राजेश बजाज

इंटेलिजेंट माइंड ट्रस्ट
दिल्ली



श्री दीपक खेतान

आल गोवा गवर्नमेंट रेकॉगनाइज़्ड
अनएडेड स्कूल्स एसोसिएशन
गोवा



श्री योगेशभाई पटेल

द गुड ह्यूमन बीईंग फाउंडेशन
ऑफ स्कूल्स
गुजरात



श्री दीपक राजगुरु

स्वनिर्भर शाला संचालक
मंडल
गुजरात



**श्री भरतभाई मोहनभाई
गजीपाड़ा**

सेल्फ फाइनेंस स्कूल मैनेजमेंट
एसोसिएशन
गुजरात



डॉ कुलभूषण शर्मा

फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स
वेलफेयर एसोसिएशन
हरियाणा



श्री पंकज सिडाना

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
सिरसा
हरियाणा



डॉ गुलशन कुमार
इंडिपेंडेंट स्कूल्स
एसोसिएशन
हिमाचल प्रदेश



श्री अजय गुप्ता
जॉइंट कमिटी ऑफ प्राइवेट
स्कूल्स
जम्मू और कश्मीर



श्री शौकर चौधरी
जम्मू और कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स
कोऑर्डिनेशन कमिटी
जम्मू और कश्मीर



डॉ जी एन वार
प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन
जम्मू और कश्मीर



श्री विनय राज मोदी
एसोसिएशन ऑफ अनप्लेड
सीबीएसई स्कूल्स
मध्य प्रदेश



श्री अनिल गर्ग
स्कूल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी
एडवाइजर निसा
महाराष्ट्र



श्री शशि कुमार
KAMS - एसोसिएट मैनेजमेंट
ऑफ इंग्लिश मिडियम स्कूल्स
कर्नाटक



श्री रामदास कादिरुर
ऑल केरल सेल्फ फाइनेंसिंग
स्कूल्स फेडरेशन
केरल



श्री सत्यन
केरला इंडिपेंडेंट स्कूल्स
अलायन्स
केरल



श्री सुनील ओलिया
ग्वालियर प्राइवेट स्कूल
एसोसिएशन समिति
मध्य प्रदेश



श्री अनिल धूपर
एसोसिएशन ऑफ अनप्लेड
सीबीएसई स्कूल्स
मध्य प्रदेश



श्री राजेंद्र सिंह
इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल्स
एसोसिएशन
महाराष्ट्र



श्री भरत मलिक
प्राइवेट अनप्लेड स्कूल्स
मैनेजमेंट एसोसिएशन
महाराष्ट्र



श्री बिथुंगो किकोन
ऑल नागालैंड प्राइवेट
स्कूल एसोसिएशन
नागालैंड



श्री कुलवीर चंद
पंजाब इंडिपेंडेंट स्कूल्स
एसोसिएशन
पंजाब



श्री अनिरुद्ध गुप्ता
एसोसिएशन ऑफ हेड्स ऑफ
रेकोगनाइज्ड एंड एफिलिएटेड स्कूल्स
पंजाब



श्री संजीव सैनी
कौंसिल ऑफ रेकोगनाइज्ड
इंडिपेंडेंट स्कूल्स
पंजाब



श्री अनिल चोपड़ा
सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स
एसोसिएशन
पंजाब



श्री वरुण भारती
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
बरनाला
पंजाब



श्री जगदीश राय शर्मा
पंजाब एफिलिएटेड रेकोगनाइज्ड
स्कूल्स एसोसिएशन
पंजाब



श्री मितुल दीक्षित
मोहाली प्राइवेट अनप्लेड
स्कूल्स एसोसिएशन
पंजाब



श्रीमती हेमलता शर्मा
स्कूल क्रांति संघ
राजस्थान



श्री कोडाराम भाट्ट
स्कूल एजुकेशन वेलफेयर
एसोसिएशन
राजस्थान



श्री सत्यमूर्ति
एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स
मैनेजमेंट
तमिलनाडु



श्री जॉन जेवियर थंगराज
क्रिस्चियन माइनोंरिटी
इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन
तमिलनाडु



श्री शेखर राव
तेलंगाना रेकोगनाइज़्ड स्कूल्स
मैनेजमेंट एसोसिएशन
तेलंगाना



श्री मार्टिन कैनेडी
तमिलनाडु नर्सरी प्राइमरी मैट्रिक
एचआर. सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट
एसोसिएशन
तमिलनाडु



श्री अतुल श्रीवास्तव
एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट
स्कूल्स
उत्तर प्रदेश



श्री अशोक मलिक
एसोसिएशन ऑफ रेकोगनाइज़्ड
प्राइवेट स्कूल्स सहारनपुर
उत्तर प्रदेश



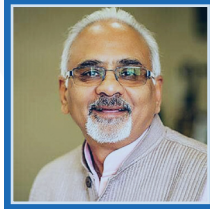
श्री दीपक मधोक
पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर
एसोसिएशन
उत्तर प्रदेश



श्री महेंद्र नंद जायसवाल
महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स
एसोसिएशन
उत्तर प्रदेश



श्री प्रदीप कुमार
मिर्जापुर स्कूल्स
एसोसिएशन
उत्तर प्रदेश



डॉ सुशील गुप्ता
एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव
स्कूल्स ऑफ आगरा
उत्तर प्रदेश



श्री थॉमस सी जे
इंडिपेंडेंट स्कूल्स एलायंस
उत्तर प्रदेश



श्री विनोद अग्रवाल
मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ
प्राइवेट स्कूल्स
उत्तर प्रदेश



श्री बलविंदर सिंह
कानपुर प्राइवेट स्कूल्स
एसोसिएशन
उत्तर प्रदेश



श्री प्रवीण अग्रवाल
पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट
सोसाइटी
उत्तर प्रदेश



श्री विवेक यादव
इटवा सीबीएसई स्कूल
एसोसिएशन
उत्तर प्रदेश



श्री सुबा सिंह
प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट
एसोसिएशन
उत्तराखंड



श्री मनोज कुमार खेरा
उधम सिंह नगर इंडिपेंडेंट
स्कूल्स एसोसिएशन
उत्तराखंड



श्री समरजीत
डेवलपिंग स्कूल्स
एसोसिएशन
उत्तराखंड



श्री बसंत बल्लभ भट्ट
तराई इंडिपेंडेंट स्कूल
वेलफेयर सोसाइटी
उत्तराखंड



श्री रामेश्वर लोधी
परवटन स्कूल एसोसिएशन
उत्तराखंड



श्री तपन घोष
वेस्ट बंगाल अनपेड स्कूल्स
एसोसिएशन
वेस्ट बंगाल

हम 1 लाख बजट निजी स्कूलों
की आवाज हैं
62 राज्य संघ
20 करोड़ छात्र
भारत के 26 राज्यों में

एसोसिएशन के लिए निसा सदस्यता फॉर्म

निसा संघ से जुड़ने के लाभ

1. बजट निजी स्कूलों के हित की वकालत करते हुए एक राष्ट्रीय आवाज प्रदान करने वाले गठबंधन में शामिल होना।
2. संघों की जरूरतों के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर।
3. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एसोसिएशन के लिए प्रतिष्ठा-निर्माण।
4. एक्सपोजर और विभिन्न राज्यों के अन्य सदस्य संघों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के अवसर।
5. शिक्षा विकास, नए कानून, नीतियों, विनियमों, संशोधनों और संबंधित मुद्दों के बारे में नवीनतम जानकारी।
6. देश भर में और पूरे देश में सहयोगियों के साथ सीधा संपर्क - लोगों और संसाधनों के लिए एक खुला प्रवेश द्वार जो स्कूलों को बेहतर बनाने में मदद करता है, एक राष्ट्रव्यापी वकालत अभियान के माध्यम से और संघों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच।
7. एक राष्ट्रीय नागरिक मंच पर प्रतिनिधित्व जो सरकार, मीडिया, शिक्षाविदों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कम नियमों और अधिक पारदर्शिता की वकालत करता है।
8. सरकारों के साथ बैठकों में भाग लेने वाले गठबंधन अधिकारियों और कर्मचारियों से महत्वपूर्ण मामलों पर अपडेट।



डिजिटल फॉर्म
भरने के लिए
QR स्कैन करें

उपलब्ध
सदस्यता

- व्यक्तिगत सदस्यता
- एसोसिएशन सदस्यता
- कॉर्पोरेट सदस्यता

निसा नमस्कार के लिए सदस्यता फॉर्म

1. अपने स्कूल की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली आदि को साझा करने के लिए आदर्श मंच।
2. शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और शिक्षकों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालना।
3. स्कूल के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट स्थान।
4. कई विशेषज्ञों के साथ सहयोग।

छह इश्यू के लिए वार्षिक सदस्यता
शुल्क - 590/- रुपये

भुगतान के प्रकार

UPI

Cheque



डिजिटल फॉर्म
भरने के लिए
QR स्कैन करें

स्कूल विकास कार्यक्रम



**Launch My
Career**



OPPORTUNITY
EduFinance



EkaLavya
IMPACT WHERE IT MATTERS



HEALTHBASIX

कार्यक्रमों का विवरण प्राप्त करने के
लिए QR स्कैन करें



Doctors as Teachers: Good health made infectious in schools

“Schools are not to teach how to earn a living, but to teach how to live”

It's just past noon at the Cygnet Public School JSPM, in Pune. The students of class 5 are listening to a story about Rakhi – another class 5 student, who has begun to feel tired quickly. “Have you heard of anaemia?” asks the teacher, “It can affect how you grow, learn and play” she explains.

Meet Dr Raksha, a medical doctor who is also a school health teacher! She is part of AddressHealth, India's leading school health provider, which offers a workbook-based curriculum for health education in schools.

Health education in schools



Health education is integral to the primary mission of schools. It must provide young people with the knowledge and skills they need to become successful learners and healthy and productive adults. Healthy students learn better, play better and miss school less often.

Health is a part of our school curricula already. But often an academic approach defeats its very purpose. In contrast, a health curriculum designed and delivered by health professionals with focus on practical knowledge and behaviour change, can make a bigger impact on students.

Doctors as health teachers in schools

AddressHealth education is workbook-based health education program in schools for students of Class 1 to 10. It is delivered by health professionals in eight periods spread out over one academic year. This ensures that it is accurate, relevant and practical. It aims at shaping individual values and group norms about health.

Parents appreciate this, making it easier for school managements to **introduce the health education curriculum in their school by including into book list.**

AddressHealth Education Workbook based curriculum for classes 1-10

Unlike a textbook, the AddressHealth education workbook

Contains essential health information conveyed through real life stories, situation, dialogues or poems. Each chapter has specific key objectives, learning outcomes and a target health behaviour change.

The layout consists of a reading/discussion activity (facilitated by the health professional in school), a class activity (to recall and reflect) and a home activity (to involve parents and reinforce the health concept).

¹http://www.cdc.gov/healthyyouth/hecat/pdf/HECAT_Overview.pdf
accessed on 17.11.04

The curriculum is designed by public health experts, paediatricians, psychiatrists, doctors, dentists and psychologists. It is comprehensive with seven broad themes for each class namely, **My Body, My Smile, My Mind, Eating Right, Germs and Diseases, Habits for Life and Staying Safe. Puberty and adolescence workshops** are conducted separately for boys and girls for classes 6, 7 & 8.

It covers health issues peculiar to our society and offers practical solutions in the Indian scenario. For example, eat seasonal and local fruits and vegetables for better health, try Indian millets- the super grains or behave well around stray dogs.

Back to Dr Raksha.

She explains how Rakhi beats anaemia. She encourages the students to identify and try various local greens. She talks about how eating a fruit with their meals can help their body absorb the iron better and also that chicken liver is great source of iron.

More than **60,000 children** across India are now covered by AddressHealth education. The entire package is priced at **less than 1 rs per child**, per year. It includes a **workbook for every child and 8 classes by the doctor.**

AddressHealth also offers medical room services, annual health check for students, and school emotional and mental wellbeing programs.

For more information, please contact
vanchana@addresshealth.com or call **9172849521**

Our services: Medical Room, Health Education, Health Check & Mental Health Workshop

Operating in: Bangalore | Delhi | Pune | Hyderabad |

T: +91-80-22444232 www.addresshealth.in

service@addresshealth.com | Follow us :    

Contact on -9172849521





**Looking to
transform
your school
as per
NEP 2020
guidelines?**



Get A Free Consultation Now!

Call

72089 47367

Scan the Code



TRUSTED BY

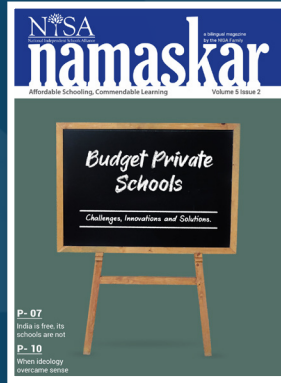
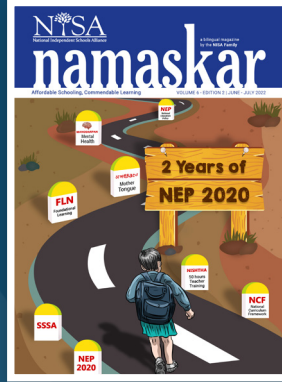
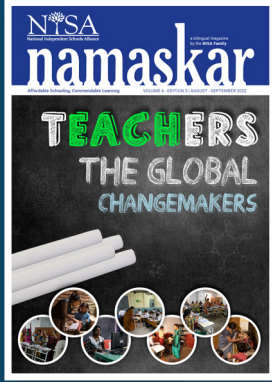
**3000+
Schools**

**400+
Cities**

**1.2 Million+
Students**

For more details, visit www.leadsschool.in

हमारी पिछली पत्रिकाएँ पढ़ें



पढ़ने के लिए QR स्कैन करें



National Independent Schools Alliance

प्रधान कार्यालय

एच-1ए/1, यूनिट नंबर- 501-503, 5वीं मंजिल
सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301
info@nisaindia.org | www.nisaindia.com